कमल संदेश
ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक

संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य

सत्यपाल

कला संपादक

धर्मेन्द्र कौशल
विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-
त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

InL;rk : +91(11) 23005798
Qku (dk-) : +91(11) 23381428
QDI : +91(11) 23387887
पता : डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003

ई–मेल

kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक – प्रभात झा

विषय–सूची

रैलियां

परिवर्तन रैली, सुजानपुर (हिमाचल प्रदेश)..... 7
विजय संकल्प समावेश : भुवनेश्वर (ओडिशा)..... 9
भारत गेलिसी रैली, दावणगेर (कर्नाटक)..... 10
महाजागरण रैली, असम..... 11

संसद में बहस : आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2014

सुषमा स्वराज, लोकसभा में विपक्ष की नेता..... 13

मुद्दा : अंतरिम रेल बजट

अनंत कुमार..... 15

लेख

डा. मनमोहन–सोनिया के नेतृत्व में संसद की गरिमा रसातल में पहुंची
–**लालकृष्ण आडवाणी**..... 16
नाकामियों से किनारा
–**जगमोहन सिंह राजपूत**..... 18
चुनावी त्रासदी के खलनायक केजरीवाल
–**अम्बा चरण वशिष्ठ**..... 20
बदल गया कांग्रेस का समय
–**अशोक मलिक**..... 22
आखिरी उम्मीद भी अधूरी
–**डॉ. मनीषा प्रियम**..... 24

अन्य

श्री नरेन्द्र मोदी के साथ अमेरिकी राजदूत सुश्री नैंसी पॉवेल ने की भेंट..... 26
सीआईआई राष्ट्रीय परिषद बैठक..... 27
नासकॉम इंडिया लीडरशिप फोरम..... 29

कमल संदेश के सभी पाठकों को

होली

की हार्दिक शुभकामनाएं!

बोध कथा

चाणक्य ने कहा, रुपया नहीं इस धन से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं

एक बार आचार्य चाणक्य से किसी ने पूछा, मानव को स्वर्ग प्राप्ति के लिए क्या उपाय करने चाहिए? चाणक्य ने बताया, जिसकी पत्नी और पुत्र आज्ञाकारी, सद्‌गुणी तथा अपनी उपलब्ध संपत्ति पर संतोष करते हों, वह स्वर्ग में नहीं, तो और कहां वास करता है।

आचार्य चाणक्य सत्य, शील और विद्या को लोक-परलोक के कल्याण का साधन बताते हुए नीति वाक्य में लिखते हैं, यदि कोई सत्यरूपी तपस्या से समृद्ध है, तो उसे अन्य तपस्या की क्या आवश्यकता है?

यदि मन पवित्र है, तो तीर्थाटन करने की क्या आवश्यकता है? यदि कोई उत्तम विद्या से संपन्न है, तो उसे अन्य धन की क्या आवश्यकता है? वह कहते हैं, विद्या, तप, दान, चरित्र एवं धर्म (कर्तव्य) से विहीन व्यक्ति पृथ्वी पर भार है। विद्यया लभते सर्व विद्या सर्वत्र पूज्यते। यानी विद्यारूपी धन से सब कुछ प्राप्त होता है।

आचार्य सदाचार और शुद्ध भावों का महत्व बताते हुए लिखते हैं, भावना से ही शील का निर्माण होता है। शुद्ध भावों से युक्त मनुष्य घर बैठे ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। भाव की प्रधानता के कारण ही पत्थर, मिट्टी और लकड़ी से बनी प्रतिमाएं भी देवत्व को प्राप्त करती हैं। अतः भाव की शुद्धता जरूरी है।

आचार्य चाणक्य का यह भी कहना है कि यदि मुक्ति की इच्छा रखते हो, तो विषय वासना रूपी विद्या को त्याग दो। सहनशीलता, सरलता, दया, पवित्रता और सच्चाई का अमृतपान करो।

-शिवकुमार गोयल

(अमर उजाला से साभार)

व्यंग्य चित्र

केजरीवाल बेनकाब!

अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर जिस प्रकार से वे मुख्यमंत्री की अपनी जिम्मेदारियों से भागे हैं उससे दिल्ली की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। ऐसे भी राजनैतिक गलियारों में उनके इस्तीफा देने की चर्चा गरम थी क्योंकि वे सरकार का कामकाज संभाल नहीं पा रहे थे और लोगों में दिन-प्रतिदिन असंतोष काफी बढ़ता जा रहा था। जिस तरह से केजरीवाल ने अपने झूठे वादों से जनता की उम्मीदें काफी बढ़ा दी थीं, वैसे में जनलोकपाल के नाम पर ड्रामा कर मैदान से भागने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं बचा था। अपने मुख्यमंत्री के छोटे से कार्यकाल में जिस तरह से केजरीवाल ने जनता को त्राहिमाम करने को मजबूर किया, इसमें कोई दो मत नहीं कि आने वाले चुनावों में भी जनता अपना बदला चुकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी।

अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा जनता के साथ छलावा तो था ही साथ ही अपनी नाकामयाबियों को छुपाने का एक बहाना भी था। शासन करने के मिले अवसर से भागकर न केवल उनकी अक्षमता उजागर हुई है बल्कि लोगों के मसले पर उनकी गंभीरता पर भी प्रश्न खड़े हो गए हैं। जनलोकपाल के मुद्दे पर वे आम सहमति बनाने का प्रयास कर सकते थे परन्तु यह जानते हुए भी कि उनके द्वारा लाया गया जनलोकपाल विधेयक कानून की परीक्षा में फेल हो जाएगा, उन्होंने जल्दबाजी में ऐसा कदम उठाया ताकि शासन की जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाकर वे इस मुद्दे पर राजनीति कर सकें। यह रवैया न केवल गैर-जिम्मेदाराना था बल्कि उनकी अवसरवादिता एवं स्वार्थपरक राजनीति को उजागर करता है। अपने लम्बे-चौड़े वादों को पूरा करने के स्थान पर वे अपनी जिम्मेदारियों से भाग गए तथा अब अपनी विफलताओं एवं अक्षमताओं का ठीकरा दूसरों के माथे फोड़ने की जुगत कर रहे हैं।

ड्रामेबाजी और सनसनीपूर्ण राजनीति में माहिर केजरीवाल को शासन जैसा गंभीर काम रास नहीं आया। उन्होंने तरह-तरह की नौटंकी से अपने दोषी मंत्रियों को बचाने का जुगाड़ किया जिससे कि उनकी छवि जनता के बीच काफी गिर गई। क्या कोई सोमनाथ भारती जैसे व्यक्ति, जिसने कानून को अपने हाथ में लेते हुए युगांडा की दो महिलाओं को जबरदस्ती पकड़ ड्रग टेस्ट करवाया, उसे बचाने की सोच भी सकता था? अपने मंत्रियों को बचाने के लिए वे धरना पर बैठ गए और जब देखा कि उनकी बेतुकी मांग नहीं मानी जा सकती तो धरने से उठ भी गए। एक तरफ जहां वे दिल्ली पुलिस के भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग का एलान कर रहे थे वहीं दूसरी तरफ वे इतने से ही मान गए कि दो पुलिसवालों को छुट्टी पर भेज दिया जाए। दिल्ली के जन-जीवन को बाधित कर उन्हें क्या हासिल हुआ? यह पूरी तरह से राजनैतिक नौटंकीबाजी थी।

केजरीवाल सरकार जनता की अपेक्षाओं पर पूरी तरह से विफल साबित हुई। अपने लंबे-चौड़े वादों को पूरा करने के नाम पर केवल आधे-अधूरे कदम उठाकर उन्होंने लोगों को मूर्ख बनाने का खेल खेला। अरविंद केजरीवाल शुरू से ही इन मामलों में गंभीर नहीं थे, वे केवल लोगों को गुमराह कर उनका वोट हासिल करना चाहते थे। उनका चेहरा पूरी तरह से तब उजागर हो गया जब अपने दावों के विपरीत उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल से पांच रूम के दो डुप्लेक्स फ्लैटों (कुल दस रूम) आवंटित करने की प्रार्थना की। असल में ये फ्लैट उन्हें आवंटित भी हो गए थे और वे उसमें जाने की तैयारी कर रहे थे परन्तु भारी जनविरोध ने उनके हाथ बांध दिए। वे कभी भी अपनी कही हुई बातों पर कायम नहीं दिखे और जब भी स्थितियां उनकी पकड़ से बाहर जाती दिखीं उन्होंने बातों को घुमा-फिरा कर अपनी जान छुड़ाई। वास्तव में में यदि देखा जाए तो 'आआपा' सरकार पर दिल्ली के लिए न तो कोई विजन था न ही कार्यक्रम या योजना। सुशासन के लिए जरूरी क्षमता और जज्बा

भी उनमें कभी नहीं दिखा। जन भागीदारी के नाम पर 'आआपा' ने गुण्डागर्दी और भीड़ की मानसिकता को बढ़ावा दिया जो लोकतांत्रिक मर्यादाओं, सिद्धांतों और संविधान के विरुद्ध था।

अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा वास्तव में एक तीर से कई शिकार करने की एक सोची-समझी राजनीति का हिस्सा है। अब जबकि 'आआपा' स्वयं को शासन के झंझटों से मुक्त पा रही है, इसका लक्ष्य श्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा के विजय रथ को रोकना है। 'आआपा' और कांगेस के बीच असल में अंदरूनी सांठ-गांठ है। अपने जन्म से ही यह कांग्रेस के धुन पर नाचती आ रही है ताकि देश में चल रहे कांग्रेस विरोधी माहौल को छिन्न-भिन्न किया जा सके। लेकिन लोग अब इनकी राजनीति समझ रहे हैं और बार-बार मूर्ख नहीं बनेंगे। 'आआपा' और कांग्रेस दोनों बेनकाब हो चुके हैं। लेकिन जनता को इनके साजिशों से सावधान रहना पड़ेगा। हर कार्यकर्ता को सावधान रहते हुए जनता में विश्वास कायम करना होगा तथा पार्टी का जनाधार बढ़ाते रहना पड़ेगा। देश अब इस नापाक गठजोड़ के छलावे में आना बर्दाश्त नहीं कर सकता। लोग श्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा की तरफ आशा और उत्साह से देख रहे हैं। हर कार्यकर्ता को बिना थके काम में जुटे रहना पड़ेगा ताकि यह उत्साह एक महान भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर सके। ■

मोदी की रैलियों ने देश का मूड पकड़ा

✍ अरुण जेटली

भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेन्द्र मोदी के लिए पिछला सप्ताह काफी व्यस्तता से भरा रहा। गत 8 फरवरी को वह इम्फाल, गुवाहाटी में थे और अंत में उन्होंने चेन्नई में रैलियों को संबोधित किया। 9 फरवरी को चेन्नई के एक शिक्षण संस्थान में एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उन्होंने कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में विभिन्न समारोहों को संबोधित किया।

इन सार्वजनिक समारोहों में नरेन्द्र मोदी के प्रति जनता का भारी उत्साह देखने को मिला। इम्फाल की रैली को मणिपुर में सबसे बड़ी राजनैतिक रैली माना जा रहा है। भाजपा का संगठन मणिपुर में बहुत मजबूत नहीं है। इसके बावजूद मोदी की रैली में भारी भीड़ का जुटना जनता के मूड को बताता है। गुवाहाटी और चेन्नई में पार्टी की रैलियों में और अंत में केरल में उन्होंने विशाल भीड़ को आकर्षित किया। उनके अन्य समारोहों ने धार्मिक और जाति के आधार पर बांटने वालों को चुनौती दी। जिन समुदायों में पहले भाजपा को कम समर्थन देखने को मिलता था, वहां लोगों ने अपने समारोहों में बड़े उत्साह के साथ उन्हें आमंत्रित किया।

कांग्रेस से लोगों का मोहभंग हो चुका है। लोग उम्मीद से देख रहे हैं। क्या श्री मोदी उस विश्वास का प्रतीक हैं जिसका उत्साहित जनता को इंतजार है? लोग कद्दावर, प्रेरणा देने वाला और निर्णायक नेता चाहते हैं।

कांग्रेस से लोगों का मोहभंग हो चुका है। लोग उम्मीद से देख रहे हैं। क्या श्री मोदी उस विश्वास का प्रतीक हैं जिसका उत्साहित जनता को इंतजार है? लोग कद्दावर, प्रेरणा देने वाला और निर्णायक नेता चाहते हैं। वे ईमानदारी के मानक नये सिरे से तय करना चाहते हैं? मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था में ठहराव जैसी चीजें उन्हें परेशान कर रही हैं। देश के उत्तरी, मध्य और पश्चिमी भागों में भाजपा के गढ़ों में मोदी की रैलियों में भारी भीड़ का जुटना स्वाभाविक है लेकिन जिन इलाकों में भाजपा परम्परागत दृष्टि से मजबूत नहीं है उन इलाकों में मोदी की ऐसी जबरदस्त रैलियों का क्या अर्थ निकाला जा सकता है? पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में मोदी की रैलियों में लोगों की भारी भीड़ और लोगों की प्रतिक्रिया रोमांचित कर देने वाली रही? क्या इस झुकाव को कुछ और समझा जा सकता है?

निश्चित तौर पर ऐसी विशाल भीड़ यूं ही नहीं जुट सकती? यह एक मजबूत अंतर्प्रवाह का संकेत है, जो गुस्से और विश्वास के कारण पैदा हुआ है। लोग यथास्थिति से नाराज हैं। वे बदलाव चाहते हैं। मोदी ऐसे बदलाव और विश्वास का प्रतीक है जो बेहतरी के लिए होगा। मोदी के पीछे राजनैतिक समर्थन को अब इस चुनाव में मोदी के लिए मत संग्रह में बदलने की जरुरत है। उन राज्यों में समाज के विभिन्न वर्गों का समर्थन भाजपा की ताकत से ज्यादा बड़ा है। क्या हम इन क्षेत्रों में सुखद आश्चर्य की तरफ बढ़ रहे हैं?■

(लेखक राज्य सभा में विपक्ष के नेता हैं)

रैलियां

भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेन्द्र मोदी देश भर में पार्टी द्वारा आयोजित विशाल जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। श्री मोदी के भाषण में ताजगी है, उत्साह है और एक महान भारत बनाने की प्रतिबद्धता झलकती है। वे अपने भाषणों में गुजरात में स्वयं द्वारा किए गए अभूतपूर्व विकास की कहानी एवं अटलजी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हैं तो वर्तमान केंद्र सरकार की नाकामियों पर करारा प्रहार करते हैं। श्री मोदी की जनसभाओं में जनज्वार उमड़ पड़ता है। हर जनसभा में लाखों लोग उन्हें सुनने आते हैं। हम यहां हाल ही में हुई उनकी चार जनसभाओं के संक्षिप्त समाचार प्रकाशित कर रहे हैं:-

परिवर्तन रैली, सुजानपुर (हिमाचल प्रदेश)

तेलंगाना मुद्दा कांग्रेस के 'जहर की खेती' करने का सटीक उदाहरण : नरेंद्र मोदी

भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर वोटबैंक की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आंध्रप्रदेश के विभाजन पर मचा बवाल इस बात का सटीक उदाहरण है कि कैसे सत्तारूढ़ दल जहर का बीज बोती है।

श्री मोदी ने हिमाचल के सुजानपुर में 16 फरवरी को एक रैली में कहा, 'आपने वोट बैंक की राजनीति शुरू की और अब आप हम पर दोषारोपण कर रहे हैं।' उन्होंने कहा, 'यह कांग्रेस ही है जो जहर का बीज बोती है। आंध्रप्रदेश यह साबित करने के लिए बिल्कुल सटीक उदाहरण है कि आप 'जहर की खेती' करते हैं।'

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर प्रहार करते हुए श्री मोदी ने कहा, 'मैडम कह रही हैं कि अगला चुनाव एकता के लिए है और यह कि हम (भाजपा) जहर का बीज बोते हैं।' उन्होंने कहा, 'लेकिन यह (जहर की खेती) कौन कर रहा है? किसने यह शुरू किया? किसने भाइयों, राज्यों के बीच

मतभेद पैदा किया? किसने धनी और गरीबों के बीच मतभेद की दीवार खड़ी की?' उन्होंने कहा कि राजग के शासनकाल में तो तीन नए राज्य बिल्कुल आसानी से बन गए। जब भाजपा ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बंटवारा किया, तब तो कोई बवाल खड़ा नहीं हुआ।

श्री मोदी ने कहा, 'भाजपा प्यार, न कि घृणा की राजनीति करती है।' उन्होंने कांग्रेस पर नफरत और छुआछूत की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, 'एक दिन, केरल के एक नेता ने मेरी प्रशंसा कर दी, उन्हें हटा दिया गया। केरल के एक मंत्री ने मुझसे भेंट की, उनकी खबर ले ली गई। नफरत और छुआछूत की इस तरह की राजनीति लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है।'

उन्होंने कहा कि कांग्रेस वंशवादी पार्टी है और वंशवादी राजनीति लोकतंत्र की दुश्मन है। श्री मोदी ने महंगाई को लेकर संप्रग सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने तो 100 दिनों में महंगाई कम करने का वादा किया था, लेकिन वह कर नहीं पाई।

उन्होंने कहा, 'पिछले 60 साल में कांग्रेस ने विकास के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन भाजपा 60 महीने में सबकुछ बदल देगी'। भ्रष्टाचार और कालेधन का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा, 'इस देश में भ्रष्टाचार की मुख्य जड़ कांग्रेस पार्टी है। यदि कांग्रेस नेता भ्रष्ट नहीं हैं, तो उन्हें कालेधन को लेकर क्यों चिंता खाए जा रही है'?

उन्होंने कहा, 'इन लोगों ने गरीबों को लूटा और विदेश में काला धन छिपा दिया। हमें उसे वापस लाना है। वेतनभोगी और नियमित रूप से कर का भुगतान करने वालों को देश में लाए जाने वाले कालेधन से इनाम मिलेगा।' श्री मोदी ने कहा, 'देश को तोड़ने की राजनीति के दिन लद गए.. भाजपा केवल विकास की राजनीति के लिए कटिबद्ध है'।

उन्होंने लोगों से रोजगार और भ्रष्टचारमुक्त भारत के लिए वोट डालने का आह्वान करते हुए कहा, 'हम देश को नयी ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए कटिबद्ध हैं...

मैं यहां आपके पास वादे लेकर नहीं आया हूं बल्कि एनडीए को नेशनल डेवलपमेंट एलायन्स बनाने के संकल्प के साथ आया हूं'।

श्री मोदी ने कटाक्ष करते कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते हैं कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, लेकिन हिमाचल प्रदेश के नेता (मुख्यमंत्री) ने अपनी आय में 14 गुणा वृद्धि दिखायी, यानी पैसे तो पेड़ पर ही उगे न।

श्री मोदी ने 'पूर्व सैनिकों' को संबोधित करते हुए कहा, 'यह योद्धाओं और शहीदों की जमीन है। जिन पूर्व सैनिकों ने भाजपा का हाथ थामा है, मैं उनका स्वागत करता हूं। यह ऐसी पार्टी नहीं है जहां सदस्यता नहीं, बल्कि लोगों में संबंध है'।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार ने देश को खोखला कर दिया है। कांग्रेस का भ्रष्टाचारी रूपी कीचड़ इतना हो गया है कि देश की जनता अब इसमें हर जगह कमल खिलाना चाहती है। उन्होंने जनता से आग्रह किया कि उनकी नजर उम्मीदवार पर नहीं नरेन्द्र मोदी पर होनी चाहिए। प्रदेश की जनता चारों सीटों पर विजय पताका फहराएगी इसका उन्हें पूरा विश्वास है।

पूर्व मुख्यमंत्री श्री शांता कुमार ने कहा कि दुनिया में सबसे भ्रष्ट देश का इस समय भारत बन गया है। इससे दुनियाभर में भारत का नाम कांग्रेस ने कलंकित किया है। कोयला की बंदरबाट से देश को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। अब यहां से कोयला तक नहीं निकाल पा रहे यह बाहर से मंगवाना पड़ रहा है। केन्द्र सरकार के कार्यकाल में सिर्फ भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा भूखे लोग भारत में रहते हैं।

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि कुशासन का दूसरा नाम कांग्रेस है। इसने पूरी दुनिया में देश का नाम बदनाम किया है। उन्होंने कहा कि अटल ने दुनिया में जो स्थान बनाया था। दस वर्षों में कांग्रेस ने भारत को कलंकित किया है। कांग्रेस शासन में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया कि उसके शून्य गिनना भी मुश्किल हो गया। टूजी, थ्रीजी के बाद जीजा जी घोटाला भी हो गया।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री सत्तपाल सत्ती ने कहा कि देश व प्रदेश की जनता की आशाएं नरेन्द्र मोदी से जुड़ी हुई हैं। हर कोई उन्हें देश का प्रधानमंत्री देखना चाहता है। पहले कांगेस के लोग मोदी को चाय बेचने वाला बोलते थे, लेकिन अब वे माफी मांग रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं बोला था। उन्होंने मनमोहन से पूछा कि वह चीन व पाक की सीमा पर कितनी बार गए।

उन्होंने कहा कि अगली बार नरेन्द्र मोदी हिमाचल में गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री बनकर आएंगे।

भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अटल की तरह ही नरेन्द्र मोदी का भी हिमाचल से बेहद लगाव रहा है। इसके चलते प्रदेश की चारों सीटें हिमाचल मोदी की झोली में डालेगा। ■

विजय संकल्प समावेश : भुवनेश्वर (ओडिशा)

'100 दिन के बाद दिल्ली में सरकार बदल जाएगी'

भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में तीसरा मोर्चा पर जमकर हमला बोला। श्री मोदी ने उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में 11 फरवरी को भाजपा की 'विजय संकल्प समाबेश' रैली को संबोधित करते हुए सबसे पहले उड़िया भाषा में जनता का अभिवादन किया।

भाजपा के पीएम उम्मीदवार ने अपनी चिरपरिचित शैली में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सरकार की नाकामियों को जनता के सामने उजागर किया। उन्होंने कहा कि क्या कारण है कि यहां का नौजवान उड़ीसा छोड़कर गुजरात जाता है।

श्री मोदी ने कहा कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और मेरा अनुभव 14 वर्षों का बराबर है लेकिन फिर भी यहां का विकास क्यों नहीं हो पाया जबकि गुजरात आज दूसरों को रोजगार दे रहा है।

भुवनेश्वर की रैली में मौजूद भीड़ से हामी भरवाते हुए श्री मोदी ने राज्य सरकार की कई नाकामियां गिनवाई। उन्होंने कहा कि यहां बेरोजगारी, अशिक्षा, पानी की कमी, नौजवानों का रोजगार पाने के लिए बाहर पलायन, मां बहनों की इज्जत सलामत नहीं आदि कई समस्याएं हैं। लेकिन ये सब देखकर बीजू पटनायक की आत्मा दुखी होती होगी।

गौरतलब है कि बीजू पटनायक अब इस दुनिया में नहीं हैं हालांकि इससे पहले वह भी प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। श्री मोदी ने कहा प्रदेश का विकास ही बीजू बाबू को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

श्री मोदी ने कहा कि देश का पूर्वी इलाका गरीब है जबकि पश्चिमी सम्पन्न। पश्चिमी इलाकों में राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा और गुजरात यहां सभी जगह भाजपा की सरकारें हैं। वहीं पूर्वी इलाके में ज्यादातर कांग्रेस या तीसरा मोर्चा की सरकारें हैं। जब मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे पिछड़े राज्यों का विकास हो सकता है तो उड़ीसा का क्यों नहीं?

श्री मोदी ने कहा कि पूर्वी इलाकों में वह लोग हैं जो थर्ड फ्रंट की दुकान खोल लेते हैं। थर्ड फ्रंट वालों को अपने प्रदेश में मुंह दिखाने की ताकत नहीं होती। पूरे पांच साल कांग्रेस की वकालत करते रहते हैं वहीं थर्ड फ्रंट की नकाब चुनाव के समय ओढ़ लेते हैं।

श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस में संकट आ जाता है तो उसे बचाने के लिए थर्ड फ्रंट आ जाता है। जबतक इन सब लोगों को पहचानेंगे नहीं हम राजनीति का शुद्धीकरण नहीं कर पाएंगे।

श्री मोदी ने कहा 2014 का चुनाव सांसदों का चुनाव नहीं राजनीतिक शुद्धीकरण का चुनाव है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हमें सिखाया कि गरीब की भलाई करो। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि है। श्री मोदी ने संबलपुर हादसे का जिक्र करते हुए प्रदेश सरकार की नाकामियां गिनायी।

श्री मोदी ने मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के विकास की

सराहना करते हुए कहा दोनों नक्सल एरिया होने के बावजूद वहां विकास हुआ। ये दोनों राज्य बढ़ सकते हैं तो उड़ीसा क्यों नहीं बढ़ सकता। छत्तीसगढ़ में आज इतना चावल है कि पूरे देश का पेट भरता है।

श्री मोदी ने कहा मध्यप्रदेश कभी बीमारू राज्य माना जाता था लेकिन आज इस प्रदेश को कोई बीमारू राज्य कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। शिवराज सिंह ने प्रदेश की विकास दर 2 से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया।

श्री मोदी ने कहा आजाद भारत ने कांग्रेस का मॉडल, साम्यवादियों का मॉडल देखा है और भाजपा का मॉडल देखा है। सबने दिल्ली को सरकार दिया है। दुनिया के अर्थशास्त्रियों को निमंत्रण देता हूं कि बताए किसने भारत का विकास किया। देश का सबसे अधिक विकास हुआ है तो सिर्फ भाजपा के समय। श्री मोदी ने कहा कांग्रेस को 60 साल

दिए हैं मुझे सिर्फ 60 महीने चाहिए। हम 60 महीनों में इस प्रदेश का विकास करके दिखाएंगे।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार ने देश को खोखला कर दिया है। कांग्रेस का भ्रष्टाचारी रूपी कीचड़ इतना हो गया है कि देश की जनता अब इसमें हर जगह कमल खिलाना चाहती है। उन्होंने जनता से आग्रह किया कि उनकी नजर उम्मीदवार पर नहीं नरेन्द्र मोदी पर होनी चाहिए। प्रदेश की जनता चारों सीटों पर विजय पताका फहराएगी इसका उन्हें पूरा विश्वास है।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने कहा स्वतंत्र भारत में कांग्रेस नीत यूपीए शासन मे जितने सारे भ्रष्टाचार हुए हैं, उतना भ्रष्टाचार और किसी शासनकाल में नहीं हुआ है। उड़ीसा में भी माइंस स्कैम हुआ है। यज जितना बड़ा घोटाला हुआ है, इसकी जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। ■

भारत गेलिसी रैली, दावणगेर (कर्नाटक)

'कांग्रेस पहले धूल झोंकती थी, अब मिर्च झोंक रही'

भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना मुद्दे से आहत आंध्रप्रदेश के लोगों के दर्द को लेकर कांग्रेस पर करारा प्रहार किया और कहा कि सोनिया गांधी एवं उनके पुत्र राहुल गांधी को 'घाव पर मलहम' लगाने के लिए उनके बीच आने तक का वक्त नहीं है।

श्री मोदी ने 18 फरवरी को यहां एक रैली में कहा, ''दो दिन पहले कांग्रेस के महानुभाव कर्नाटक आए थे, कांग्रेस अध्यक्ष भी दक्षिण में थीं लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि मैडम सोनिया और राहुल दोनों दक्षिण में आते हैं लेकिन उनके पास आंध्रप्रदेश आने का वक्त नहीं होता।'' उन्होंने कहा, ''आज हमारे सीमांध्र और तेलंगाना के भाइयों को कांग्रेस द्वारा उन्हें दिए गए दर्द पर मलहम लगाने की जरुरत है लेकिन उनके पास उन पर मलहम लगाने के लिए थोड़े से शब्द भी नहीं हैं।''

भाजपा नेता ने कांग्रेस को याद दिलाया कि 2009 में आंध्रप्रदेश में भारी जीत से ही उसे केंद्र में सरकार बनाने में मदद मिली थी।

श्री मोदी ने कहा, ''आज जब आंध्रप्रदेश के लोग दिक्कत में हैं तो कांग्रेस नेताओं का उनसे बातचीत करने का मूड नहीं है। कांग्रेस ऐसी स्थिति में है कि उन्हें लोगों की संवेदनाओं और परेशानियों की कोई परवाह नहीं है।'' राहुल गांधी को घेरते हुए उन्होंने कहा, ''यह महानुभाव कर्नाटक आए और उन्होंने महिलाओं के लिए अपनी चिंता प्रकट की। यदि आपको महिलाओं की इतनी ही चिंताएं हैं तो आप महंगाई नीचे लाइए ताकि हमारी माताएं और बहनें राहत महसूस करें।'' दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के बढ़ते मामलों के लिए कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ते हुए उन्होंने कहा, ''आपने तो दिल्ली को बलात्कार की राजधानी बना दी और इसकी वजह से भारत की बदनामी हो रही है।''

कांग्रेस और भ्रष्टाचार को जुड़वा बहनें करार देते हुए उन्होंने कहा, ''जहां कहीं कांग्रेस जाएगी, वहां भ्रष्टाचार भी जाएगा और जहां भ्रष्टाचार होगा, वहां कांग्रेस होगी ही।

जबतक हम खुद को कांग्रेस से मुक्त नहीं कर लेते, देश भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हो सकता।''

उन्होंने इस आरोप का सिरे से खंडन किया कि भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक भाजपा की वजह से पारित नहीं हो पाया। उन्होंने कहा, ''कम से कम, जनता के सामने सच बोलने की आदत विकसित कीजिए। देश इन दिनों देख रहा है कि कौन संसद बाधित कर रहा है और उसे काम नहीं करने दे रहा।'' श्री मोदी ने कहा कि संसद में मिर्च स्प्रे करने वाले कांग्रेस के सांसद हैं। ■

महाजागरण रैली, असम

'मनमोहन सिंह ने 23 वर्षों में असम के लिए कुछ नहीं किया'

प्रधानमंत्री पद के लिए भाजपा के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को निशाना बनाते हुए उन पर असम के लिए कुछ भी नहीं करने का आरोप लगाया जिसका वह गत 23 वर्षों से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

श्री मोदी ने कहा कि ऐसे नेता से देश क्या उम्मीद कर सकता है। श्री मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, अब तो केवल 100 दिनों की बात है। कांग्रेस का जाना तय है। वे नहीं बचेंगे।

उन्होंने डॉ. सिंह पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि असम से यदि किसी सामान्य कार्यकर्ता ने इतने वर्षों तक राज्य का प्रतिनिधित्व किया होता तो उसने राज्य की तस्वीर बदल दी होती लेकिन सिंह ऐसा करने में असफल रहे और उन्हें इसके लिए जनता को जवाब देना चाहिए।

श्री मोदी ने यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से पूछा, आप 23 वर्षों से प्रधानमंत्री को यहां से भेज रहे हैं। आप मुझे बताइये, आपने इतना बड़ा निवेश किया लेकिन आपको इसका प्रतिफल क्या मिला। आपको क्या कुछ मिला?...यदि उन्होंने आपके होते हुए आपके लिए कुछ नहीं किया तो वह देश के लिए क्या करेंगे।

उन्होंने कहा, सभी पूर्वोत्तर राज्यों में असम की स्थिति सबसे खराब है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, कांग्रेस के नेता संकीर्ण मानसिकता वाले हैं। उनकी सोच संकीर्ण है, सपने छोटे और दृष्टि अदूरदर्शी है।

उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी यदि असम से एक छोटा कार्यकर्ता भी राज्यसभा में 23 वर्षों तक बैठता हो उसने असम की तस्वीर बदल दी होती।

आप राज्यसभा में 23 वर्षों से बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री का प्रतिष्ठित पद पर आसीन हैं और इसके बावजूद आपका राज्य असम इतनी खराब स्थिति का सामना कर रहा है, तब आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि यह देश कितनी खराब स्थिति में होगा।

श्री मोदी ने कहा कि लोकतंत्र में असम और देश के लोगों को यह अधिकार है कि वे प्रधानमंत्री से स्पष्टीकरण मांगे कि वह उनके उम्मीदों पर खरा उतरने में असफल क्यों रहे।

गुजरात के मुख्यमंत्री श्री मोदी ने महाजागरण समावेश रैली को संबोधित करते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी आपको

जवाब देना होगा। देश की जनता को आपसे जवाब मांगने का अधिकार है और असम के लोगों को आपसे जवाब मांगने का विशेष अधिकार है। उन्होंने अपना हमला असम और केंद्र दोनों ही स्थानों की सरकारों पर हमले पर केंद्रित रखा।

श्री मोदी ने कहा, आपने कांग्रेस को 60 वर्षों तक झेला। उन्होंने केवल वादे किये और देश को गुमराह किया। आप मुझे केवल 60 महीने दीजिये, मैं आपकी आकांक्षाओं को पूरा कर दूंगा।

उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, वे काला धन विदेशों में जमा कर रहे हैं और उसे वापस नहीं ले आना चाहते।

भाजपा सरकार काला धन भारत वापस लाने के लिए सब कुछ करेगी और उसे विभिन्न विकास कार्यों में लगाएगी। काले धन को गरीबों, शिक्षा के प्रसार और वृद्धों को भोजन और दवा मुहैया कराने के लिए खर्च करेगी। ■

अंतरिम बजट पर वक्तव्य

निर्माण और कृषि क्षेत्र रहा उपेक्षित : राजनाथ सिंह

''अंतरिम बजट'' पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह द्वारा 17 फरवरी 2014 को जारी वक्तव्य

वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने आज सदन में जो लेखानुदान मांगें प्रस्तुत कीं वह यूपीए सरकार की विफलताओं पर पर्दा डालने का एक असफल प्रयास था। उन्होंने आंकड़ों की बाजीगरी करके वर्ष 2013-14 के लिए 4.6 प्रतिशत का वित्तीय घाटा दिखा दिया। उन्होंने अगले वित्तीय वर्ष के लिए 35000 करोड़ रुपये की ईंधन सब्सिडी से जुड़े वित्तीय करारनामे की शर्तो पर पुन: समझौता किया ताकि बेहतर वित्तीय आंकड़े दिखाई दें।

यहां तक कि 2014-15 के लिए रखा गया उनका 4.1 प्रतिशत वित्तीय घाटे का लक्ष्य विश्वसनीय नहीं लगता क्योंकि उन्होंने अपने कुल सब्सिडी बिल को 2.46 लाख करोड़ रुपये रखा है जो उतना ही है जितना इस वर्ष था जिसमें उन्होंने 35000 करोड़ रुपये की ईंधन सब्सिडी को शामिल नहीं किया। 3.3 प्रतिशत का राजस्व घाटा इस बात का स्पष्ट संकेत है कि सरकार ने अपनी वित्तीय फिजूलखर्ची पर लगाम लगाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। यूपीए सरकार अपने योजनागत खर्च में जबरदस्त कटौती करके वित्तीय लक्ष्यों के बराबर पहुंच पाई है। इसका अर्थ है कि सरकार ने अर्थव्यवस्था में अपने निवेश कम कर दिए हैं।

भूतपूर्व सैनिकों को 'एक रैंक एक पेंशन' की घोषणा स्वागत योग्य फैसला है। सरकार इस मुद्दे से पिछले कई वर्षो से अपने आपको दूर रखे हुए थी लेकिन जब बाद में उसे अहसास हुआ कि भाजपा 'एक रैंक एक पेंशन' देने के लिए प्रतिबद्ध है तो आज उसने इसकी सहमति दे दी।

निर्माण और कृषि क्षेत्र दो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें देश में लाखों लोगों को रोजगार मिलता है और इन्हें प्राथमिकता के आधार पर पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश अंतरिम बजट में इन दोनों को लेकर कोई स्पष्टता और दिशा नहीं बताई गई है।

हांलाकि श्री चिदम्बरम ने भारतीय निर्माण क्षेत्र की दुर्दशा को सही पहचाना है लेकिन वे इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं बता पाए। यूपीए सरकार ने 2011 में राष्ट्रीय निर्माण नीति की व्याख्या की थी लेकिन उसके बाद के वर्षो में कुछ खास नहीं किया गया। अंतरिम बजट में कहा गया है कि दिल्ली-मुंबई कोरीडोर के अलावा आठ राष्ट्रीय निर्माण जोनों को मंजूरी दी जा चुकी है लेकिन हम सभी जानते हैं कि मंजूरी मिलने और निर्णय में देरी के कारण समूची परियोजना बेहद धीमी गति से चल रही है।

निर्माण और कृषि क्षेत्र दो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें देश में लाखों लोगों को रोजगार मिलता है और इन्हें प्राथमिकता के आधार पर पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश अंतरिम बजट में इन दोनों को लेकर कोई स्पष्टता और दिशा नहीं बताई गई है।

बीमार कृषि क्षेत्र के लिए वास्तव में कोई घोषणा नहीं की गई है। देश के किसानों को आज खेती से निश्चित आमदनी, संस्थागत सहायता और सस्ते ऋण की आवश्यकता है। अंतरिम बजट में केवल कृषि ऋण के लिए करीब 8 लाख करोड़ रुपये की राशि बढ़ाने की बात कही गई है लेकिन ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। चूंकि भाजपा का मानना है कि लोकसभा चुनावों के बाद वह अगली सरकार का गठन करेगी। हम देश की जनता को आश्वासन देना चाहते हैं कि हम अर्थव्यवस्था के सामने मौजूद सभी प्रमुख मुद्दों का हल निकालेंगे और अर्थव्यवस्था को उच्च वृद्धि दर की ओर ले जाएंगे। ■

संसद में बहस

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2014

भाजपा इस विधेयक का समर्थन करती है : सुषमा स्वराज

गत 18 फरवरी 2014 को लोकसभा में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2014 पारित किया गया। लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज ने विधेयक पर चर्चा आरंभ करते हुए कहा कि भाजपा इस विधेयक का समर्थन करती है। हम उनके भाषण का सारांश यहां प्रकाशित कर रहे हैं:

मैं अपनी पार्टी की ओर से आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2014 का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। हम बिल का समर्थन भी करेंगे और इस बिल को पारित करने के लिए इसके पक्ष में मतदान भी करेंगे। क्योंकि यह विषय हमारी विश्वसनीयता से जुड़ा हुआ विषय है। दसियों बार इस सदन के अंदर और बाहर, तेलंगाना के अंदर और तेलंगाना के बाहर हमने यह मांग की है कि सरकार तेलंगाना निर्माण का बिल लेकर आए, भारतीय जनता पार्टी अपना समर्थन देकर उसको पारित कराएगी। केवल यही नहीं, हमने यह भी कहा कि अगर यह सरकार बिल लेकर नहीं आएगी तो जब हमारी सरकार आएगी तो हम सौ दिनों में तेलंगाना निर्माण करेंगे। मैं जब यहां तेलंगाना के लिए बोल रही थी, तेलंगाना के लिए आत्मदाह करने वाले बच्चों से अपील करते हुए मैंने कहा था कि तेलंगाना का निर्माण कराने के लिए आत्महत्या मत करो, तेलंगाना को देखने के लिए जीवित रहो।

आज जब यह बिल उनके सपनों को साकार करने के लिए आया है तो इसका विरोध करके हम उन बच्चों के साथ विश्वासघात कैसे कर सकते हैं? हालांकि मैं कुछ बातें रिकॉर्ड में लाना चाहती हूं। मेरी पहली शिकायत कांग्रेस नेतृत्व से है। आपने 2004 में तेलंगाना देने का वादा किया था, 2014 आ गया। 21 तारीख को सत्रावसान हो जाएगा, आज 18 है, केवल तीन दिन बाकी हैं। आप विषय को खींचते-खींचते यहां तक ले आए और लाए भी कैसे, अपने लोगों को भी मनाए बिना। आप अपने सांसदों को नहीं मना सके, आप अपने मंत्रियों को नहीं मना सके, आप अपने मुख्यमंत्री को नहीं मना सके। किसी संसद ने यह दृश्य नहीं देखा होगा कि प्रधानमंत्री सदन में बैठे हों और उनके मंत्रिमंडल के मंत्री सदन के वैल में खड़े हों। यहां तक कि कांग्रेस की अध्यक्षा सदन में बैठी हों और उनके सांसद उनकी परवाह किए बिना सदन के वैल में खड़े हों, उनके मुख्यमंत्री धरने पर बैठे हों। प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट से बिल पारित करें और उनके अपने मुख्यमंत्री बिल को रिजेक्ट करके और रद्द करके भेज दें। हमने भी तीन राज्य बनाए थे। रक्त की एक बूंद नहीं गिरी थी, एक क्षण के लिए सदन में अशांति नहीं हुई थी।

भारतीय जनता पार्टी के सीमांध्र के कार्यकर्ता और नेता भी यह कह रहे हैं कि तेलंगाना बनना चाहिए और हैदराबाद भी तेलंगाना को मिलना चाहिए। मगर उनके साथ भी न्याय करो और वे न्याय के लिए क्या मांगते हैं, वे यह कहते हैं कि हैदराबाद में अगर 15 हजार करोड़ का सरप्लस है तो तेलंगाना का घाटा उससे पूरा हो जायेगा, लेकिन कोस्टल आंध्र और रायलसीमा का घाटा कौन पूरा करेगा। वह केन्द्र सरकार पूरा करे।

दूसरी बात वे कहते हैं कि हैदराबाद में 148 संस्थाएं हैं, दस साल के लिए वह ज्वाइंट कैपिटल है, लेकिन उनके यहां भी जो संस्थाएं बननी हैं, उनका इन प्रिंसिपल अप्रूवल प्लानिंग कमीशन से दो और थोड़ी टोकन राशि रखकर इसे इंटेरिम बजट में उनका बजट हैड बना दो। मैं कहना चाहूंगी कि इस बिल में कानूनन एक कमी है। यह बिल संविधान की स्कीम को बदलकर गवर्नर को कुछ ऐसी शक्तियां दे रहा है, जो संविधान में संशोधन करके ही दी जा सकती हैं। हमने सरकार से कहा है कि आप साधारण बिल की बजाय अगर संविधान संशोधन भी लाते हो तो हम साथ देंगे, हम संविधान संशोधन भी पारित करायेंगे, मगर डिफैक्टिव बिल मत लाओ। ■

लेखानुदान पर टिप्पणी

चिदम्बरम का लेखानुदान अगले वित्त मंत्री के लिए परेशानियां खड़ी करेगा : अरुण जेटली

वित्त मंत्री ने 17 फरवरी को संसद में लेखानुदान अनुमानों को प्रस्तुत किया। उनके लिए यह यूपीए सरकार के 10 वर्षों की उपलब्धियों को प्रस्तुत करने का एक चुनावी उल्लेख करने जैसा था। उन्हें कड़ी वास्तविकता का सामना करना पड़ा। उन्हें विरासत में 8.5 प्रतिशत जीडीपी की विकास दर मिली थी। अब वह 4.5 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि छोड़कर जा रहे हैं। यूपीए के पिछले तीन वर्षों में विकास दर में भारी गिरावट देखने को मिली है, जो 9 प्रतिशत से गिरकर 5 प्रतिशत तक जा पहुंची। अत:, उन्हें कड़ा नारा देकर पीछे झुकना पड़ा जैसे 'भारत के बारे में मेरा विचार'। स्पष्ट है कि किसी भी वैचारिक बहुवादी समाज में एक से अधिक 'आइडिया आफ इण्डिया' हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी पुस्तक को शीर्षक पर अपना कब्जा नहीं जमा सकता है और यह दावा कर सकता है कि इस पर तो केवल मेरा ही अधिकार है।

वित्त मंत्री ने पिछले वर्ष स्वयं अपने लिए लक्ष्मण-रेखा खींच ली थी। राजकोषीय घाटे को 4.8 प्रतिशत तक लाना था। अब उनका दावा है कि इसे 4.6 प्रतिशत तक ले आया गया है। उन्होंने यह कमाल राजस्व बढ़ा कर या निवेश-चक्र को पुनर्जीवित करके नहीं किया है बल्कि उन्होंने खर्च में, विशेष रूप से पूंजी खर्च में कटौती करके किया है। पूंजी एसेट्स और पूंजी खर्च के अनुदान को 9100 करोड़ तक की कटौती कर डाली है। अकेले इससे ही

17 फरवरी 2014 को श्री चिदम्बरम द्वारा लेखानुदान पर दिए गए भाषण पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली की टिप्पणी

जीडीपी पर 0.8 प्रतिशत तक का दुष्प्रभाव पड़ जाएगा। इसी प्रकार, वर्तमान वर्ष के विभिन्न मंत्रालयों के आवंटन में वर्ष 2013-14 के बजट अनुमानों और 2013-14 के संशोधित अनुदानों में भारी अंतर है। पेयजल मंत्रालय के अनुदान में 21.3 प्रतिशत तक की कटौती कर डाली है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में की गई कटौती 20.6 प्रतिशत है। आवास और नगरीय निर्धनता उन्मूलन की कटौती 41.97 प्रतिशत, गृहमंत्रालय की कटौती 31.3 प्रतिशत, मानव संसाधन मंत्रालय की कटौती छह प्रतिशत, सड़क परिवहन और राजमार्गों की कटौती 18.72 प्रतिशत और ग्रामीण विकास मंत्रालय की कटौती 22.92 प्रतिशत की गई है। ये सभी के सभी विभाग और मंत्रालय सामाजिक क्षेत्र तथा इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं। केवल वित्त मंत्रालय के अनुदान में 18.3 प्रतिशत बढ़ाई गई है।

इसके बाद राज्यों के अनुदानों में 1,36,254 करोड़ रुपए के बजट अनुमानों में से घटाकर 1,19,039 करोड़ रुपए कर दी गई है जो 12.6 प्रतिशत की कमी दर्शाती है।

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कम करना एक बड़ा चिंता का विषय है। इससे रोजगार पर सीधा असर पड़ता है। वर्तमान वर्ष की एक्साइज ड्यूटी, जिसका 1,97,554 करोड़ रुपए रह गई है जिसका मतलब है 9.1 प्रतिशत की कमी।

वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र में अद्भुत प्रदर्शन का श्रेय लेने की कोशिश की है, परन्तु यह श्रेय गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को जाता है जिन्होंने कृषि में दो अंकों में विकास करके दिखाया है।

2014-15 के लिए खाद्य, उर्वरक और ईंधन पर सब्सिडी के बारे में 2,46,397 करोड़ रुपए बताया गया है। इसमें में ईंधन सब्सिडी 65,000 करोड़ रुपए है। उर्वरक पर 36,970 करोड़ रुपए और खाद्य सब्सिडी 1,15,000 करोड़ रुपए है। सभी खाद्य योजनाओं के संयुक्त खर्च 2013-14 में 1,24,844 करोड़ रुपए से कम कर के 2014-15 में 1,15,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यह खाद्य सुरक्षा योजना की

शेष पृष्ठ 30 पर

अंतरिम रेल बजट मात्र दिखावा और स्टंट है : अनंत कुमार

मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा पेश अंतरिम रेल बजट चुनावी लफ्फाजी और स्टंट के अलावा और कुछ नहीं है। 'चुनावी बजट' के प्रस्ताव इतने अल्पकालीन है कि उनका कार्यान्वयन ही संदेह पैदा करता है क्योंकि अगले 15 दिनों में तो आचार संहिता लागू हो जाएगी।

हम इस अंतरिम रेल बजट का बखान यूपीए-कांग्रेस सरकार का विदाई बजट कह सकते हैं। पूरा देश आने वाले महीनों में श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार के वास्तविक रेल बजट की बाट जोह रहा है जिससे भारतीय रेल में क्रांति पैदा हो सकती है।

यूपीए के 10 वर्षों का कार्यकाल रेलवे के मामले में तो निश्चित ही कर्नाटक के लिए बदतर काल गिना जाएगा। प्राय: कहा जाता है कि गवर्नेंस की अच्छाई-बुराई सदैव उस सरकार की सेवाओं से बंधी होती है जो वह नागरिकों को प्रदान करती है और भारत में यह बात रेलवे पर अत्यधिक सही बैठती है। कर्नाटक तथा पूरे भारत के लोग लोकसभा चुनावों की बाट जोह रहे हैं जब वे श्रीमती सोनिया, डा. सिंह और श्री राहुल की त्रिमूर्ति को हटा पाएंगे क्योंकि इन्होंने अपनी अपनी अकुशलता और विजन के अभाव से पूरे देश को परेशान कर रखा है। भारत में कर्नाटक की भाजपा सरकार ही केवल एक ऐसा राज्य थी जिसने अपने राज्य बजट में से बजट आवंटन की राशि देकर सर्वाधिक मदद की थी और इतना ही नहीं उसने रेलवे परियोजनाओं के लिए नि:शुल्क

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा 2014-15 वर्ष के अंतरिम बजट पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री अनंत कुमार, सांसद द्वारा जारी वक्तव्य

भूमि का वचन दिया था और इस प्रयोजन के लिए विशेष संयुक्त विधायी समिति बनाई थी। इतना होने पर भी कर्नाटक और दक्षिणी-पश्चिमी रेलवे का सदा ही नई गाड़ियों, इलेक्ट्रिफिकेशन, डबलिंग, गेज कन्वर्जन, नई लाइनें बिछाने या यात्रियों की सुविधाओं के लिए सबसे कम हिस्सा मिला।

कर्नाटक और दक्षिण-पश्चिम रेलवे क्षेत्र ने अब तक कई वर्षों से रेलवे के रेलवे के लिए निवेश अनुपात के मामले में सर्वाधिक लाभ दिया है। परन्तु यूपीए के हर बजट में इस जोन को सबसे कम धन राशि मिली है।

सभी यूपीए सरकारों का केन्द्र के रवैय्ये के कारण यूपीए सरकारें पीपीपी परियोजनाएं बनाने में विफल रही हैं। उदाहरणार्थ, हालांकि कर्नाटक सरकार ने भूमिका आवंटन कर और अपने राज्य बजट से धनराशि देकर अद्वितीय विकास परियोजनाएं बनाई, फिर भी रेलवे ने अपने हिस्से का योगदान नहीं किया जिसके कारण बहुत लम्बे समय से ये परियोजनाएं पैण्डिंग पड़ी रहीं।

बंगलौर के लिए उपनगरीय रेल सेवा के लिए कर्नाटक सरकार ने परियोजना लागत का 50 प्रतिशत राशि देने की वचनबद्धता दर्शाई और इसी प्रकार बंगलौर-मैस्कर और बंगलौर-टुमकुर रेल कारीडोर में दोहरी लाइनें बिछाने, बिजलीकरण और आटोमैटिक सिग्नलिंग व्यवस्था में भी ऐसा किया, फिर भी इन सभी की उपेक्षा की गई।

कर्नाटक क्षेत्र के मामले में 8वां सबसे बड़ा राज्य है परन्तु उत्तर-पूर्व तथा जम्मू और कश्मीर को छोड़कर चौथा न्यूतम रेल सघनता का क्षेत्र है।

इस बजट में कटरा के लिए एक साप्ताहिक ट्रेन सर्विस को छोड़ कर अभी तक भी कर्नाटक के लिए किसी भी डेस्टीनेशन से सीधी सेवा नहीं है, जैसे अमृतसर, जम्मू तवी, देहरादून और वाराणसी से कर्नाटक तक कोई सेवा उपलब्ध नहीं है। यह तो तब है जब कि बंगलौर सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला शहर है, जिसकी आईटी और सर्विसेज उद्योग पूरे भारत के लोगों के

शेष पृष्ठ 30 पर

डा. मनमोहन-सोनिया के नेतृत्व में संसद की गरिमा रसातल में पहुंची

लालकृष्ण आडवाणी

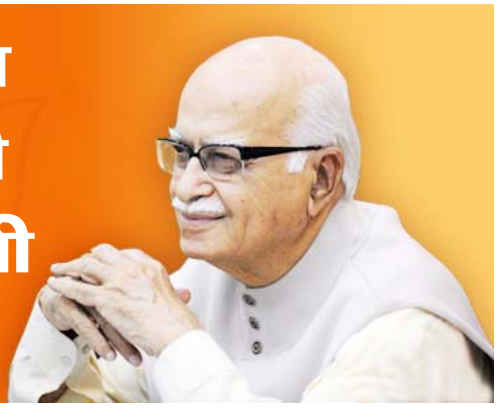

सन् 2004 से अब तक यानी 2014 तक के दस वर्षों में यू.पी.ए. सत्ता में है। यू.पी.ए.-I सन् 2004 से 2009 और यू.पी.ए.-II सन् 2009 से 2014।

डा. मनमोहन सिंह ने अपनी पारी की शुरुआत निजी तौर पर एक साफ सुथरी छवि से की थी। परन्तु जैसे-जैसे उनका एक दशक लम्बा कार्यकाल समाप्ति की ओर है तो वह अपने पीछे स्वतंत्र भारत में सर्वाधिक भ्रष्ट सरकार का मुखिया होने का रिकार्ड छोड़ कर जाएंगे।

दिल्ली में राष्ट्रमण्डल खेलों के दौरान उजागर हुए घोटाले से शुरू होकर, 2जी स्पैक्ट्रम घोटालों सहित कांग्रेस सरकार में हुए अधिकतर घोटालों का पर्दाफाश सी.ए.जी. या न्यायपालिका द्वारा किया गया और इसमें साफ हुआ कि सरकार के मंत्रियों/अफसरों ने घूस देने वालों को लाभ पहुंचा कर कथित रूप से घूस ली।

परन्तु मैं मानता हूं कि यू.पी.ए.-1 के कार्यकाल के दौरान सर्वाधिक शर्मसार करने वाला काण्ड था-नोट के बदले वोट। यह उस समय घटित हुआ जब यू.पी.ए. सरकार द्वारा वाशिंगटन से परमाणु सौदा करने के चलते वाम मोर्चे ने अपना समर्थन वापस लेने का फैसला किया।

इसके फलस्वरूप डा. मनमोहन सिंह की सरकार के सामने गंभीर संकट पैदा हुआ और उन्हें विश्वास मत का सामना करना पड़ा जिसमें हो सकता था कि उनकी सरकार की छुट्टी हो जाती।

इस बिन्दु पर भारत-अमेरिकी परमाणु सौदे से जुडे भारत सम्बन्धी राजनयिक 'केबल्स' को व्हिसल ब्लोअर वेबसाइट विकीलीक्स द्वारा जारी कर दिया गया और जिसे भारत के चेन्नई से प्रकाशित होने वाले प्रतिष्ठित समाचार पत्र 'दि हिन्दू' ने हुबहु प्रकाशित किया। **इस सम्बन्ध में रायटर ने इस प्रकार रिपोर्ट दी:**

विकीलीक्स द्वारा हासिल किए गए गोपनीय अमेरिकी विदेश विभाग के केबल्स और 'दि हिन्दू' समाचार पत्र द्वारा वीरवार को प्रकाशित केबल्स में एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता तथा अमेरिकी दूतावास के एक अधिकारी के बीच विश्वासमत का सामना करने वाली सरकार द्वारा एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल से समर्थन लेने की एवज में लगभग 9 मिलियन अमेरिकी डॉलर के भुगतान से सम्बन्धी वार्तालाप का ब्यौरा दिया गया है।

विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज, जो पिछले कुछ महीनों से कांग्रेस नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार पर भारत में भ्रष्टाचार से लड़ने में असफलता को लेकर हमले कर रही हैं, ने ट्विट किया है: ''आज के हिन्दू में प्रकाशित सांसदों को पैसे देने की विकीलीक्स की रिपोर्टें शर्मनाक हैं। आज मैं इस मुद्दे को संसद में उठाऊंगी।''

इन केबल्स के ब्यौरों को लेकर मचे हो-हल्ले के चलते वीरवार को संसद के दोनों सदन 30 मिनटों के लिए स्थगित हो गए।

केबल्स में कांग्रेस पार्टी के सांसद और पार्टी की प्रमुख सोनिया गांधी के निकट सहयोगी सतीश शर्मा और अमेरिका के चार्ज डि अफेयर स्टीवन व्हाइट के बीच की बातचीत का ब्यौरा है। जिसमें एक सहयोगी बताता है कि राष्ट्रीय लोकदल के चार सांसदों को भारत और अमेरिका के बीच परमाणु सौदे के फलस्वरूप लाए गए विश्वासमत पर समर्थन में वोट देने के लिए सामान रूप से 100 मिलियन रूपये (2.2 मिलियन डालर) से दिए गए।

इस गोपनीय केबल्स के लेखक व्हाइट ने वर्णन किया कि कैसे दूतावास के स्टाफ को 500-600 मिलियन रूपयों (11-13 मिलियन डॉलरों) के दो बैग यह कह कर दिखाए गए कि इन्हें 'भुगतान के लिए' रखा है।''

मेरे सहयोगी श्री सुधीन्द्र कुलकर्णी के साथ ही तीन भाजपा सांसद इस

काण्ड का पर्दाफाश करने के अभियान में शामिल थे। उन्होंने इस घूसखोरी काण्ड की वीडियो रिकार्डिंग हेतु एक टी.वी. चैनल से सम्पर्क साधा। सरकार ने जो कदम उठाया, वह यह कि इन सबको जेल भेज दिया। जब न्यायाधीश श्री नरोत्तम कौशल ने इन्हें रिहा करने का फैसला सुनाया, उसका शुरूआती पैराग्राफ निम्न है:

22 जुलाई, 2008 भारतीय संसद के इतिहास में एक काला दिन है। संसद के तीन सदस्यों अशोक अर्गल, फग्गन सिंह कुलस्ते और महावीर सिंह भगौरा ने सदन में जब विश्वासमत पर बहस हो रही थी तब एक करोड़ रुपये के करेंसी नोट सदन पटल पर रखे। यह दावा किया गया कि यह रकम उन्हें सदन में वोट देने के बदले प्रस्तावित की गई। सदन के स्पीकर ने वरिष्ठ सांसदों के साथ विचार-विमर्श कर इन तीनों सांसदों को लिखित शिकायत देने को कहा। इससे पहले कि इन तीनों सांसदों द्वारा लिखित शिकायत सौंपी जाती, स्पीकर महोदय को सीएनएन-आईबीएन नेटवर्क के मुख्य सम्पादक राजदीप सरदेसाई का एक पत्र 23 जुलाई, 2008 को प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने इस पत्र के साथ पांच वीडियो टेप भी भेजे थे। इन तीनों सांसदों ने स्पीकर महोदय को 25 जुलाई, 2008 को अपनी औपचारिक शिकायत सौंपी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सरकार की सहायता करने के उद्देश्य से विश्वासमत के विरोध में मतदान न करने के बदले रिश्वत देने की कोशिश की।

जैसे ही मुझे, मेरी पार्टी के तीन सांसदों और सुधीन्द्र कुलकर्णी जैसे मेरे निकट सहयोगी की गिरफ्तारी का पता चला तो मैंने आदरणीय स्पीकर महोदय से किसी भी अन्य कार्यवाही शुरू होने से पूर्व संक्षेप में अपना पक्ष रखने की अनुमति मांगी। गुस्से में, मैंने कहा कि एक भयंकर अपराध रचा गया और सांसदों को सरकार का समर्थन करने के लिए करोड़ों रूपये की घूस दी गई है। इन चारों भाजपा सांसदों ने घूस की राशि घर न ले जाकर एक व्हिसल ब्लोअर की भांति वे सीधे संसद आए और यह राशि सदन के पटल पर रख दी। दुनिया के लोकतंत्रों में व्हिसल ब्लोअरों का अभिनन्दन किया जाता है और हमारे यहां पर उन्हें जेल भेजा जा रहा है! इनका नेता होने के नाते मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि यदि वे समझते हैं कि मेरे इन सहयोगियों ने कुछ अवैध काम किया है तो मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि उन्होंने इस घृणित काण्ड को उजागर करने के लिए यह मेरी अनुमति से ही किया है। मैं सरकार को चुनौती देता हूं कि वह इन सांसदों के साथ मुझे भी जेल भेजे।

भारतीय संसद की प्रतिष्ठा और छवि पर नोट के बदले नोट काण्ड ने जो कालिख पोती थी उससे कम शर्मनाक नहीं है यूपीए-2 के शासन में घोटालों का अम्बार। वाजपेयीजी के नेतृत्व वाली एन.डी.ए. सरकार ने तीन प्रमुख राज्यों - मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार का विभाजन कर तीन नए राज्यों - छत्तीसगढ़, उत्तराखण्ड और झारखण्ड का निर्माण बगैर किसी विरोध के किया। वर्तमान सरकार के चलते, संसद के सत्र-दर-सत्र तेलांगाना के निर्माण को लेकर विभाजन समर्थकों तथा विरोधियों के बीच टकराव की भेंट चढ़ गए।

वास्तव में संसद के चालू सत्र में तेलंगाना के मुद्दे पर गत् सप्ताह जो शर्मनाक दृश्य उपस्थित हुआ उसके चलते प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह को कहना पड़ा: "जब मैं सदन में ऐसे हालात देखता हूं तो मेरा दिल खून के आंसू बहाता है।'' एक दिन संसद में अधिकतर सांसद उस समय हतप्रभ रह गए जब वर्तमान सरकार के आधा दर्जन मंत्री ने प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह और कांग्रेसाध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी को नजरअंदाज कर, सदन के 'वेल' में कूदे और आंध्र प्रदेश के विभाजन के पक्ष और विपक्ष में नारेबाजी कर रहे सांसदों के बीच पहुंचे और संसदीय कार्यवाही सम्बन्धी पत्रक फाड़कर फेंके दिए। यह 12 फरवरी, बुधवार को हुआ।

इस अशोभनीय व्यवहार ने अगले दिन तो सभी सीमाएं लांघकर, पहले दिन की भांति कांग्रेस सांसदों में से एक ने कालीमिर्च के पाऊडर का स्प्रे निकालकर छिड़कना शुरू किया, जिससे श्रीमती सुषमा स्वराज जिनकी आंखों से पानी छलक पड़ा, सहित अनेक को काफी तकलीफ पहुंची।

टेलपीस (पश्च्यलेख)

14 फरवरी को राजधानी से प्रकाशित समाचारपत्रों के कुछ शीर्षक:

दि स्टेट्समैन : पार्लियामेंट डिसग्रेस्ड। (संसद कलंकित हुई)

दि टाइम्स ऑफ इण्डिया : पिपरस्प्रे इन हाऊस लीव्स इण्डियन डेमोक्रेसी इन टियर्स। (संसद में मिर्ची पाऊडर स्प्रे ने भारतीय लोकतंत्र को आंसुओं में डुबोया)

हिन्दुस्तान टाइम्स : पार्लियामेंट अटैक्स दिस टाइम बाई एमपीस। (इस बार संसद पर हमला सांसदों द्वारा)

दि पायनियर : दि डार्कस्ट डे (सर्वाधिक काला दिन)

दि हिन्दू : एमपीस मेक इट ए डे ऑफ शेम फॉर पार्लियामेंट। (सांसदों ने इसे संसद के लिए शर्म का दिन बनाया)■

(लेखक भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष हैं।)

नाकामियों से किनारा

✍ जगमोहन सिंह राजपूत

भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के दशकों में जो उपलब्धियां सरकारी तौर पर देश और दुनिया के सामने रखी जाती हैं उनका श्रेय लेने के लिए सबसे पहले 1885 में स्थापित देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस सामने आती है, परंतु जब देश में भ्रष्टाचार, मूल्यों का हनन, गरीबों पर अत्याचार, अन्याय और चुनाव में लगातार बढ़ रहे धनबल की जिम्मेदारी की चर्चा होती है तब यह दल दूसरों पर आरोप लगा देता है। बढ़ती महंगाई के कारण कितने ही करोड़ लोग रोज भूखे सोते हैं। उनके लिए खाद्य सुरक्षा कानून का हवाला दिया जाता है और यह भुला दिया जाता है कि कभी इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा देकर सत्ता प्राप्त की थी। वह सपना कितने दशकों तक साकार नहीं हो पाया और अब नए रूप में देश के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। राहुल गांधी कहते हैं कि जो 'उल्लू' बनाए उनकी इज्जत मत करो। शायद वह भूल गए कि 1947 के बाद उनकी पार्टी यही काम करती रही है। जनता को गरीबी हटाने के सपने दिखाना इसी प्रक्रिया का उदाहरण है। देश में जो सांप्रदायिक वैमनस्य लगातार बढ़ा है और देश के सभी भागों में लगभग निरंतरता के साथ होने वाले दंगे और हिंसा को बढ़ाने में सबसे अधिक योगदान कांग्रेस पार्टी का ही रहा है। इस दल ने अपना यह उत्तरदायित्व कभी नहीं निभाया कि वह मुस्लिम संप्रदाय को वोट बैंक मानकर उन्हें केवल सब्जबाग न दिखाए, बल्कि उनकी स्थिति सुधारने के लिए संविधान में निहित निर्देशों के आधार पर कार्य करे।

कांग्रेस को यह मानना पड़ेगा कि उसने कभी भी जनतांत्रिक परंपराओं का पालन किया ही नहीं। हिंदुओं और मुसलमानों को लगातार अलग करते रहने के लिए उसने हर प्रकार के छल प्रपंच करने में कभी कोई हिचक नहीं दिखाई। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जब यह कहा कि देश के संसाधनों पर मुस्लिम समुदाय का पहला हक है तब वह किस प्रजातांत्रिक मूल्य को दृढ़ कर रहे थे, यह तो वही समझ सकते हैं। बहुसंख्यक संप्रदाय ने इसे अल्पसंख्यक तुष्टीकरण माना और मुस्लिम संप्रदाय ने महसूस किया कि उनकी तरफ फिर से चारा फेंका जा रहा है। सभी को याद है कि गुजरात में प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर जनमत के आधार पर चुने गए मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस अध्यक्षा ने 'मौत का सौदागर' कहकर उनकी दूसरी बार की जीत निश्चित कर दी थी। अभी कुछ दिन पहले एक नया वाक्य उछाला गया है जिसमें 'जहर की खेती करने वालों' पर प्रहार किया गया है। जन सामान्य इस वाक्य को भी मौत के सौदागर की श्रेणी में रखता है और इस समय प्रबुद्ध समाज में ही नहीं सामान्य जन में भी यह चर्चा आम है कि वास्तविक रूप से जहर की खेती इस देश में कौन कर रहा है?

जब पहली बार देश में प्रधानमंत्री पद पर भारतीय की नियुक्ति का अवसर आया तब 16 में से 13 प्रांतीय कांग्रेस समितियों ने सरदार पटेल का नाम सुझाया था। प्रजातांत्रिक मूल्यों का तकाजा यह था कि नेहरू स्वयं इस विशाल बहुमत को स्वीकार करते और सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनने देते, वह ऐसा करने का साहस नहीं कर पाए। बहुमत को नकारने का जो बीज उस समय बोया गया था वह लगातार वंशवाद के रूप में वट वृक्ष बन गया और इसी कारण अनेक बार परिवार को प्रजातांत्रिक मूल्य के ऊपर तरजीह दी गई। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सामान्य अपेक्षा थी कि उनके मंत्रिमंडल के सबसे वरिष्ठ मंत्री

बढ़ती महंगाई के कारण कितने ही करोड़ लोग रोज भूखे सोते हैं। उनके लिए खाद्य सुरक्षा कानून का हवाला दिया जाता है और यह भुला दिया जाता है कि कभी इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा देकर सत्ता प्राप्त की थी। वह सपना कितने दशकों तक साकार नहीं हो पाया और अब नए रूप में देश के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। राहुल गांधी कहते हैं कि जो 'उल्लू' बनाए उनकी इज्जत मत करो। शायद वह भूल गए कि 1947 के बाद उनकी पार्टी यही काम करती रही है।

प्रणब मुखर्जी तत्काल प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते, परंतु उन्हें नकार कर राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनाए गए। ऐसा तब हुआ जबकि इसके पहले दो बार गुलजारी लाल नंदा प्रधानमंत्री पद का उत्तरदायित्व ऐसी ही परिस्थितियों में निभा चुके थे। यहां पर यह याद कर लेना भी उचित होगा कि जिस प्रकार सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस के योगदान को नेहरू के समय में तथा उसके बाद भी लगातार नकारा गया वह अपने आप में परिवार-केंद्रित व्यवस्था की बड़ी कहानी कहता है। आज भी दिल्ली में बोस और सरदार पटेल का कोई भी स्मारक नहीं बना है। नेहरू-गांधी परिवार के कितने स्मारक और स्मृति स्थल दिल्ली में हैं और कितने हजार संस्थाओं, कार्यक्रमों, योजनाओं के नाम इस परिवार से जुड़े हैं, यह देश का हर सामान्य जन जानता है। आज भी लगभग प्रत्येक नई योजना, भवन, मार्ग इत्यादि का नामकरण इसी परिवार के किसी न किसी के नाम से हो रहा है।

मोदी की कार्यक्षमता ने उनकी राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय छवि बनाई है। उस छवि को पुख्ता करने, संवारने और निखारने का काम कांग्रेस ने अपनी नासमझी से बड़े मनोयोग से किया है। मणिशंकर अय्यर जैसे लोग वास्तव में मोदी के पक्ष में जमकर काम कर रहे हैं। मोदी को कांग्रेस सभास्थल पर चाय बेचने के लिए आमंत्रित कर उन्होंने करोड़ों परिवारों और मतदाताओं को मोदी की ओर मोड़ दिया। ठीक वैसे ही राहुल गांधी ने गुजरात में उल्लू बनाने वालों से बचने का उपदेश देकर गुजरात लोकसभा चुनावों में मोदी की सफलता को सुदृढ़ कर दिया है। शरद पवार जैसे लोग जनता से जुड़े होने के कारण हवा का रुख पहचान रहे हैं और वास्तविकता के अधिक करीब हैं। जनतंत्र का तकाजा है कि जनता तथा न्याय व्यवस्था पर पूरी तरह हर प्रकरण में समान रूप से विश्वास किया जाए। गुजरात की जनता के निर्णय का उतना ही महत्व है जितना कर्नाटक के लोगों का है। 1984 के सिख-संहार की विभीषिका में भी न्याय दिलाना उतना ही आवश्यक है जितना 2002 के गोधरा-गुजरात के दंगों में है। मुस्लिम समुदाय भी शिक्षित होकर, कौशल सीख कर सबके साथ आगे बढ़ना चाहता है। अब वह आश्वासनों से तंग आ गया है। देश के दोनों बड़े समुदायों के बीच अविश्वास के बीज बोने वाले ही जहर की खेती करते रहे हैं। दूसरों पर आरोप लगाकर यह किसे मूर्ख बना रहे हैं? ■

(लेखक एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक हैं।)

(दै. जागरण से साभार)

भारत बने खेल की महाशक्ति – राजनाथ सिंह

गत 20 फरवरी को रामलीला मैदान, दिल्ली में आयोजित 'खेल संसद' को सम्बोधित करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अभी दिल्ली में संसद का सत्र चलते हुए आप लोग देख रहे हैं। भिन्न-भिन्न लोकसभा क्षेत्रों से चुनकर लोग आते हैं और उन्हीं को मिलाकर संसद का गठन होता है।

लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी को खेल का संसद, खिलाड़ियों का संसद आयोजित करते आप लोगों ने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। पहली बार इस काम को यदि कोई राजनैतिक पार्टी कर रही है तो वह है भारतीय जनता पार्टी। आप सभी जानते हैं कि हिन्दुस्तान दुनिया का ऐसा देश है, जहां नौजवानों की आबादी 60-65 फीसदी से भी अधिक है। जिस देश में नौजवानों की संख्या इतनी अधिक हो, वह देश ओलंपिक या कश्वमनवेल्थ गेम्स में एक या दो गोल्ड मेडल के लिए तरसता रहे, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है?

मुझे याद है कि 2012 में जो ओलंपिक खेल हुए थे उसमें भारत को एक भी गोल्ड मेडल हासिल नहीं हुआ था। केवल छह मेडल हासिल हुए और इतने में ही हम लोगों में यहां खुशी मनाई। मैं मानता हूं कि आजादी के बाद शासन कर रही सरकारों ने अगर खेलों के विकास पर ध्यान दिया होता और खेलों, खिलाड़ियों को भी देश के मान-सम्मान और स्वाभिमान से जोड़ने का प्रयास किया होता तो भारत में नौजवान के अंदर जैसी क्षमता, प्रतिभा और कूव्वत को देखते मैं समझता हूं कि खेल की दुनिया में भारत इस विश्व का महाशक्ति बन सकता था। लेकिन इस ओर हुए अधिकांश सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। हम भारत को विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि आर्थिक महाशक्ति के साथ खेल के नजरिए से भी भारत महाशक्ति बने, यानी 'इकनोमिक सुपर पावर' के साथ-साथ 'स्पोर्टिंग सुपर पावर' भी बन जाए, इसके लिए भी पहल की जानी चाहिए। ■

चुनावी त्रासदी के खलनायक केजरीवाल

✍ अम्बा चरण वशिष्ठ

यदि राजनीति झूठे वादों का बीज बो कर राजनीति व चुनाव की भरपूर फसल काटने की कला है तो इस कला में अरविन्द केजरीवाल से अधिक निपुण कोई नहीं हो सकता जिन्होंने 14 फरवरी को दिल्ली के मुख्य मन्त्री पद से त्यागपत्र दिया। वह तो शब्दशः एक पूर्व लिखित पटकथा के अनुसार पग-पग कदमताल कर रहे थे जिसका अन्त पूर्वनिर्धारित ही था। दिल्ली का चुनाव तो एक त्रासदी थी जिसने केजरीवाल को एक खलनायक के रूप में उभार कर रख दिया। हालात ने ऐसी करवट ली कि उन्हें मुख्य मन्त्री ही बन बैठना पड़ा। उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी इसीलिये उन्होंने जनता को चांद व तारे ला देने तक के वायदे कर डाले। वह समझते थे कि उन्हें पूरा करने की नौबत तो आयेगी नहीं पर वह जनता को यह ताना अवश्य दे पायेंगे कि यदि उन्हें बहुमत दिया होता तो वह स्वर्ग को ही जनता के दरवाजे पर खड़ा कर देते।

केजरीवाल तो आन्दोलनकारी घुमक्कड़ और जन्तर-मन्तर के 'हीरो' थे जो अपने ही अहंकार व बड़बोलेपन के शिकार हो गये। वह तो मुख्य मन्त्री की कुर्सी पर बैठ कर अपने आपको बेचैन महसूस कर रहे थे। वह वाक्पटुता के धनी और कार्यपालन के दिवालिया थे जिस कारण जनता उनसे दिन-प्रतिदिन परेशान होती जा रही थी। अब उनके लिये वायदों की दुनिया वास्तव का नर्क दिखने लगी थी।

केजरीवाल ने तो यहां तक दावा कर डाला था कि उन्होंने कुछ ही दिन में वह कमाल कर दिखाया है जो पिछली सरकारें 10-15 वर्ष में भी न कर पाई थीं। पर जमीन की हकीकत तो कुछ और ही थी। उन्होंने बिजली की दरों में 50 प्रतिशत की कटौती की घोषणा तो अवश्य कर डाली पर उसका असर जनता को मिले बिजली के बिलों में दिखाई न दिया। उन्हें बिल पहले की तरह ही बढ़े हुये मिले। 700 लिटर मुफ्त पानी की कहानी भी वही थी। उल्टे बिजली व पानी की कटौती की शिकायतें पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गईं। संयोगवश जिस दिन उन्होंने पद छोड़ा उससे पहले वह 372 करोड़ रूपये की सबसिडी उन बिजली कम्पनियों को दे गये जिनके कामकाज की आलोचना वह आये दिन करते रहते थे।

केजरीवाल ने तो यहां तक दावा कर डाला था कि उन्होंने कुछ ही दिन में वह कमाल कर दिखाया है जो पिछली सरकारें 10-15 वर्ष में भी न कर पाई थीं। पर जमीन की हकीकत तो कुछ और ही थी।

हैरानी की बात तो यह है कि केजरीवाल प्रतिदिन अम्बानी की बिजली कम्पनी को बुरा-भला कहने से न चूकते थे पर टाटा की कम्पनी पर मेहरबान थे। 29 जनवरी को टाटा की कम्पनी ने सरकार को लिख कर मांग की थी कि यदि मार्च से गैस की कीमत बढ़ा दी जाती है (जो केन्द्र सरकार के अनुसार अवश्यंभावी है) तो बिजली की दर पहली अप्रैल से 28 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा दी जाये। केजरीवाल ने यह तथ्य जानबूझ कर इतने दिन जनता से छुपाये रखा।

केजरीवाल ने भ्रष्टाचार को समाप्त कर देने के मुद्दे पर जनता से जनादेश प्राप्त किया था। अपने 49 दिन के कार्यकाल में उनकी सब से बड़ी उपलब्धि है 3 पुलिस सिपाहियों को भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ लेना। इससे बड़ी उपलब्धि और हो ही क्या सकती थी।

किसी को यह आशा नहीं थी कि केजरीवाल जैसे नैतिक व्यक्ति अपनी झूठी वाह-वाह के लिये झूठ का सहारा भी ले सकते थे। उन्होंने स्वयं सीआईआई की सभा में और उनकी निकटतम सहयोगी शाजिया इल्मी ने दावा कर दिया कि ट्रांसपेरैंसी इंटरनैशनल इण्डिया ने एक सर्वे करवाया है जिसके अनुसार केजरीवाल सरकार के कार्यकाल में दिल्ली में भ्रष्टाचार बहुत कम हो गया। उन्हें तब मुंह की खानी पड़ी जब इस अन्तर्राष्ट्रीय संस्था ने साफ इनकार कर दिया कि न तो उन्होंने कोई ऐसा सर्वे करवाया है और न उसके पास कोई ऐसी रिपोर्ट ही है। हार कर केजरीवाल को उस संस्था से मुआफी मांगनी पड़ी। वरिष्ठ पत्रकार कंचन गुप्ता ने इसे ''नैतिक भ्रष्टाचार'' की संज्ञा दी है।

केजरीवाल सरकार के पद ग्रहण की पूर्व संध्या पर केन्द्र सरकार ने रसोई गैस व सीएनजी के दाम बढ़ा दिये थे। केजरीवाल ने गृहणियों व आटो चालकों को राहत देने का आश्वासन दिया था। सरकार तो चली गई पर उनके इन प्रबल समर्थकों को निराशा ही हाथ लगी।

रेल भवन के सामने अपने धरने के नाटक के बाद जो उनकी मिट्टी पलीद हुई उसके बाद उन्हें अपनी औकात समझ आ गई। उन्हें अब आभास हो गया कि वह जनता को आगे और मूर्ख नहीं बना पायेंगे और भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिये कांग्रेस द्वारा उन्हें समर्थन देते रहने की मजबूरी को भी आगे न भुना पायेंगे। इस लिये तब से वह इस ताक में थे कि कोई ऐसा बहाना ढूंढा जाये जिससे कि वह सरकार से बाहर होने का ऐसा नाटक कर पायें कि जनता को ऐसा लगे कि वह उसके लिये शहीद हो गये।

रेल भवन के सामने अपने धरने के नाटक के बाद जो उनकी मिट्टी पलीद हुई उसके बाद उन्हें अपनी औकात समझ आ गई। उन्हें अब आभास हो गया कि वह जनता को आगे और मूर्ख नहीं बना पायेंगे और भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिये कांग्रेस द्वारा उन्हें समर्थन देते रहने की मजबूरी को भी आगे न भुना पायेंगे। इस लिये तब से वह इस ताक में थे कि कोई ऐसा बहाना ढूंढा जाये जिससे कि वह सरकार से बाहर होने का ऐसा नाटक कर पायें कि जनता को ऐसा लगे कि वह उसके लिये शहीद हो गये।

एक मुख्य मन्त्री को रूप में केजरीवाल को संविधान और राष्ट्र के कानून की पूरी जानकारी होनी चाहिये थी। उन्होंने जनलोकपाल बिल का ढकोसला ढूंढा। कानून के अनुसार इस बिल को विधान सभा में प्रस्तुत करने के लिये उपराज्यपाल के माध्यम से केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक थी। इस पर उपराज्यपाल ने विधान सभा अध्यक्ष को कानून के अन्तर्गत एक ''सन्देश'' भेजा कि क्योंकि इस बिल पर उनकी व केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति नहीं है इसलिये इस बिल को विधान सभा की स्वीकृति के लिये सदन में प्रस्तुत न किया जाये। इसके बावजूद जानबूझ कर केजरीवाल ने उपराज्यपाल के पूर्वानुमति के बिना ही जनलोकपाल विधान सभा में प्रस्तुत कर दिया क्योंकि केजरीवाल को तो 'शहीद' होना था। विपक्ष ने अध्यक्ष को विवश किया कि वह उपराज्यपाल के ''सन्देश'' को सदन में रखें। इस सन्देश के दृष्टिगत विपक्ष ने केजरीवाल सरकार के संविधान व कानून की धज्जियां उड़ाने के इस पग का सम्भागी न बनने का निर्णय किया और इस बिल को विचारार्थ प्रस्तुत करने के अनुमति के विरोध में मतदान किया। पर केजरीवाल को तो जनता को गुमराह कर अपने आप को 'शहीद' जताना था। उन्होंने यह प्रापेगण्डा कर दिया कि विपक्ष ने इस बिल का ही विरोध किया।

इस प्रकार केजरीवाल व विधान सभा अध्यक्ष दोनों ही ने इस बिल को विधान सभा में प्रस्तुत कर संविधान व कानून दोनों ही का उल्लंघन किया।

ऐसा करने का उनका और भी कारण था। वह लोक सभा चुनाव के लिये अपने आपको मुख्यमन्त्री की कड़ी से मुक्त रखना चाहते थे। एक सांस में तो उन्होंने यह घोषणा कर डाली कि वह भाजपा के प्रधान मन्त्री पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी के विरुद्ध गुजरात को छोड़ कर कहीं से भी लोक सभा चुनाव लड़ेंगे। दूसरे सांस में कह दिया कि वह दिल्ली विधान सभा में ही बने रहेंगे और लोक सभा चुनाव नहीं लड़ेंगे।

याद करने योग्य है कि जब केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई थी तो डींग हांकी थी कि उनकी पार्टी में दूसरी पार्टियों की तर्ज पर कोई हाई कमान नहीं होगी और पार्टी की सभी नीतियों पर निर्णय जनता ही करेगी। पर इसका भांडा जल्दी ही फूट गया। हाल ही में आप ने लोक सभा के 20 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और जनता से कोई सलाह नहीं ली। यही कारण है कि चांदनी चौक सीट पर पार्टी के भीतर विद्रोह उमड़ पड़ा है।

हैरानी की बात तो यह है कि एक वह पार्टी देश का शासन अपने हाथ में लेकर एक स्वच्छ व स्थाई सरकार देने का वादा कर रही है जो दिल्ली सरीखे छोटे से राज्य में 49 दिन से अधिक न टिक सकी और जो जनता की आशाओं व आकांक्षाओं पर खरा उतरने में विफल रही है।

दूसरी ओर, भाजपा के प्रधान मन्त्री पद के प्रत्याशी नरेन्द्र मोदी ने अपने 14 वर्ष के गौरवशाली कार्यकाल में गुजरात में सुशासन की नींव रखी और विकास का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया। वह उसके बलबूते पर जनादेश मांग रहे हैं। उनके व्यक्तित्व व चरित्र में दूरदर्शिता है, समर्पण है और लगन है। वह जो कहते हैं वह करते हैं और जो करते हैं वही कहते हैं। ■

(लेखक भारतीय जनता पार्टी के साहित्य एवं प्रकाशन प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक हैं)

बदल गया कांग्रेस का समय

अशोक मलिक

गत 17 मई को भारत जवाहर लाल नेहरू की 50वीं पुण्यतिथि मनाएगा। तेजी से चल रहे घटनाक्रम और समाचार-चक्र के आदी हो चुके आज के भारतीयों के लिए यह कल्पना करना कठिन है कि उस समय के भारतीयों के लिए उस महान व्यक्ति का गुजर जाना क्या मायने रखता था। अपनी सभी गलतियों और उस समय चीन के हाथों शर्मिन्दा होने के बावजूद नेहरू को बेहद पसंद किया जाता था और वो एक विशुद्ध भारतीय व्यक्ति माने जाते थे। उनकी मौत से एक युग समाप्त हो गया, उग्रता का एक नया दौर शुरू हुआ और वास्तविक राष्ट्रीय शोक की लहर चल पड़ी थी।

यह आज प्रासंगिक क्यों है, एक कठोर और कटुतापूर्ण चुनावी मौसम में जबकि भारत 16वें लोकसभा के लिए मतदान की तैयारी कर रहा है? एक आश्चर्यजनक, चुभने वाले संयोग के लिए इसका उल्लेख किया जा रहा है जो न केवल तिथियों के समान होने को दर्शाएगा बल्कि भारतीय राजनीतिक इतिहास में कुछ समाप्त होने का द्योतक भी होगा। इस वर्ष मई में, शायद पंडित नेहरू की पुण्यतिथि के कुछ दिन पूर्व भारत एक नए प्रधानमंत्री को पदग्रहण करते देखेगा। मत सर्वेक्षण संकेत देते हैं कि यह नया प्रधानमंत्री कांग्रेस का नहीं होगा या कम से कम कांग्रेस का वह अवतार नहीं होगा जिस पर नेहरू के अवसान के बाद उनके परिवार का प्रभुत्व हो।

सबसे ताजा मत सर्वेक्षण जो कि 13 फरवरी को टाइम्स नाऊ और सी-वोटर द्वारा प्रसारित किया गया, वो कांग्रेस के लिए केवल 89 सीटों और भाजपा के लिए 202 सीटों की भविष्यवाणी करता है। यह संख्याएं पूरी तरह सही नहीं भी हो सकती हैं। अन्य मत सर्वेक्षण कुछ भिन्नता दर्शाते हैं। हालांकि व्यापक रूप से संकेत मिलते जुलते नजर आते हैं। कांग्रेस पर 100 सीटों से नीचे गिरने का खतरा मंडरा रहा है, जोकि अब तक का उसका सबसे खराब प्रदर्शन होगा। भाजपा के 200 सीट जीतने की भविष्यवाणी है, जोकि उसका अब तक का श्रेष्ठ प्रदर्शन होगा।

नेहरू के अवसान के 50 वर्ष बाद राजनीतिक वंश, जोकि उनके नाम व चेहरों के बल पर अभी भी कांग्रेस पर काबिज है, इसका अस्तित्व संकट में है। भारत ने दो बार जनता द्वारा इस परिवार को नकारे जाते देखा है। पहले 1977 और फिर 1989 में। 1990 के दशक में कांग्रेस की पराजय कुछ खास मायने नहीं रखती क्योंकि पार्टी का नेतृत्व, सिर्फ 1999 को छोड्कर, नेहरू परिवार के हाथों में नहीं था और राजीव गांधी के पदमुक्त होने के बाद से नेहरू गाधी परिवार का कोई भी सदस्य कार्यकारी संवैधानिक सत्ता के रूप में आसीन नहीं रहा। यदि मत- सर्वेक्षण सही हैं तो 2014 का चुनाव 1977 और 1989 की तरह या उससे भी ज्यादा पतनकारी हो सकता है। संप्रग सरकार एक दशक तक सत्ता में 100 - सीटों से नीचे रहने का खतरा मंडरा रहा है, जोकि अब तक का उसका सबसे खराब प्रदर्शन होगा। भाजपा के 200 सीट जीतने की भविष्यवाणी है, जोकि उसका अब तक का श्रेष्ठ प्रदर्शन होगा।

श्रीमती सोनिया गाधी और श्री राहुल गांधी व्यवस्था के चेहरे रहे हैं। यद्यपि उन्होंने औपचारिक रूप से सरकार में कोई पद नहीं संभाला और संप्रग से सम्बद्ध रहे। इस तरह संप्रग के खिलाफ सत्ताविरोधी लहर से प्रेरित मतदान और विशेषाधिकार की व्यवस्था एवं नेहरू गांधी सत्ता के खिलाफ कठोर जनभावनाओं के होने से इंकार नहीं किया जा सकता। यह दिखावा करना अब आसान नहीं रह गया कि लोग श्री मनमोहन सिंह से नाराज हैं और कांग्रेस अध्यक्षा और उपाध्यक्ष के प्रति उदासीन या सहानुभूति रखते हैं। होने वाली हार राजनीतिक और चुनावी ब्रांड के तौर पर नेहरू गांधी परिवार की व्यवहार्यता पर सवाल खड़े करेगी।

नेहरू के अवसान के 50 वर्ष बाद राजनीतिक वंश, जोकि उनके नाम व चेहरों के बल पर अभी भी कांग्रेस पर काबिज है, इसका अस्तित्व संकट में है। भारत ने दो बार जनता द्वारा इस परिवार को नकारे जाते देखा है। पहले 1977 और फिर 1989 में। 1990 के दशक में कांग्रेस की पराजय कुछ खास मायने नहीं रखती क्योंकि पार्टी का नेतृत्व, सिर्फ 1999 को छोड़कर नेहरू परिवार के हाथों में नहीं था और राजीव गांधी के पदमुक्त होने के बाद से नेहरू गांधी परिवार का कोई भी सदस्य कार्यकारी संवैधानिक सत्ता के रूप में आसीन नहीं रहा। यदि मत

सर्वेक्षण सही हैं तो 2014 का चुनाव 1977 और 1989 की तरह या उससे भी ज्यादा पतनकारी हो सकता है। संप्रग सरकार एक दशक तक सत्ता में क्यों बनी रही? श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी व्यवस्था के चेहरे रहे हैं। यद्यपि उन्होंने औपचारिक रूप से सरकार में कोई पद नहीं संभाला और संप्रग से सम्बद्ध रहे। इस तरह संप्रग के खिलाफ सत्ताविरोधी लहर से प्रेरित मतदान और विशेषाधिकार की व्यवस्था एवं नेहरू गांधी सत्ता के खिलाफ कठोर जनभावनाओं के होने से इंकार नहीं किया जा सकता। यह दिखावा करना अब आसान नहीं रह गया कि लोग श्री मनमोहन सिंह से नाराज हैं और कांग्रेस अध्यक्षा और उपाध्यक्ष के प्रति उदासीन या सहानुभूति रखते हैं। होने वाली हार राजनीतिक और चुनावी ब्रांड के तौर पर नेहरू गांधी परिवार की व्यवहार्यता पर सवाल खड़े करेगी। असंतुष्टों ने 1977, 1989 में भी कांग्रेस को छोड़ा था। वस्तुत: इंदिरा गांधी को पश्च आपातकाल पराजय के बाद कांग्रेस का विभाजन करना पड़ा था। हालांकि बड़ी संख्या में वफादार और एक अखिल भारतीय राजनीतिक संजाल उनके साथ रहा। उनके पुत्र संजय गांधी ने 1970 की ठगों से भरी युवा कांग्रेस से सड़क पर संघर्ष करने वाली ऊर्जा प्राप्त कर इसका निर्माण किया था। 1989 में गठबंधन युग की शुरूवात असली तौर पर नहीं हो पाई और कांग्रेस के बहुत से लोगों ने सोचा था कि राजीव गांधी अभी या बाद में सत्ता में वापस आ जाएंगे। चाहे जो भी हो, कांग्रेस हर तरह से सबसे बड़ी पार्टी बनी रही।

इन सब मामलों में 2014 अलग किस्म का खतरा पेश करता है। इस बात में विश्वास बहुत कम है कि राहुल गांधी एक निर्णय क्षमता से परिपूर्ण, स्पष्ट विचारों वाले नेता बनकर उभर रहे हैं जो जनता को ऊर्जा से भर देंगे। उनकी राजनीतिक दक्षता और चुनावी रणनीतियां आदर्शात्मक कही जाती हैं और दीर्घकालीन भी। निजी तौर पर कांग्रेस में उनके लोग उन्हें नुकसान दे रहे हैं। यदि कांग्रेस 89 सीटों तक सिमट जाती हैं तो अगले चुनाव में उसे 125 से 135 सीटों तक की बढ़ोत्तरी करनी होगी जोकि 2009 में उसे मिली 206 सीटों से काफी कम है और आगे पुराने समय की तरह पूर्ण बहुमत की पार्टी बन पाना सपना बना रहेगा। राहुल गांधी के स्थान पर उनकी बहन को लाना और यह सोचना कि वह जनता की पसंद के मामले में उनसे बेहतर हैं, शायद ही कारगर साबित होगा।

जिसकी संभावना ज्यादा है, वो है कांग्रेस के भीतर मूल रूप से शक्ति का पुनर्गठन। कोई भी राज्यस्तरीय नेता जो 2014 के बाद की परिस्थितियों में उभर कर आता है, वो या तो कांग्रेस की छत्रछाया के बाहर ऐसा करेगा या कांग्रेस से जुड़े रहने के बदले बड़ी कीमत मांगेगा। वह दिल्ली पर दबाव रखेगा। वास्तविक जीवन का एक उदाहरण दें तो यदि वाई एस राजशेखर रेड्डी आने वाले 2014 के चुनावों के बाद दिवंगत होते तो नेहरू गांधी परिवार को उनके बेटे जगनमोहन रेड्डी को आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री पद हेतु नकारना बहुत कठिन हो जाता।

आंतरिक पतन के अतिरिक्त कांग्रेस एक दृढ़ प्रतिज्ञ विरोधी का सामना कर रही है। पूर्व में पार्टी क्रो स्वतंत्र पार्टी से लेकर पुराने जनसंघ से चुनौतियां मिलीं, समाजवादियों से लेकर जनता पार्टी तक से चुनौतियां मिलीं और निश्चित, रूप से क्षेत्रीय दलों से। इन दलों का एक सीमित भौगोलिक या जनसंख्यात्मक प्रभाव रहा है। वैकल्पिक रूप से वे अल्पसमय वाली रही हैं। उनमें से बहुतों का नेतृत्व उन लोगों के हाथों से रहा जो दिल्ली की राजनीतिक संस्कृति से प्रभावित थे और जिनका निर्माण कांग्रेस और परिवार के नेतृत्व द्वारा किया गया। नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा दो तरह से इस पुराने मॉडल से भिन्न है। पहला, 12 वर्ष गुजरात पर शासन करके श्री मोदीगन केवल राजनीति में एक वैकल्पिक परम्परा का प्रतिनिधित्व करते हैं बल्कि प्रशासन में भी एक वैकल्पिक परम्परा को लेकर चलते हैं। वो पूर्व गैर कांग्रेसी नेताओं की तुलना में दिल्ली वाली व्यवस्था से स्वयं को कुछ अलग हटकर साबित करने के लिए ज्यादा उत्सुक होंगे। श्री मोदी और भाजपा में उनके समसामयिक नेता जिनमें वे मजबूत मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, जिन्होंने कुछ बड़े राज्यों, में कांग्रेस को मात दी है। वे भाजपा में दूसरी पीढ़ी का हिस्सा हैं। यह पहली अखिल भारतीय गैर कांग्रेस पार्टी ड़ै जिसने नवीनीकरण दर्शाया है। और आधारशिला रखने वाले नेतृत्व क्री उपलब्धियों के आधार पर स्वयं को निमित किया है। बहुत से अन्य कांग्रेसी विरोधियों के विपरीत यह एक या दो करिश्माई नेताओं के सेवानिवृत्त होने या गुजर जाने के बाद लुप्त नहीं हो गई।

कांग्रेस के लिए ये सभी कटु-वास्तविकताएं हैं। 17 मई, 1964 को लाखों लोग नेहरू के लिए रोए थे। मई, 2014 में उन्हीं भारतीयों के बच्चे और नाती-पोते कांग्रेस और उसके वंश से छुटकारा पाकर खुश होंगे। इतिहास ने पन्ना बदल दिया है, भारत आगे बढ़ चुका है।■

(लेखक वरिष्ठ टिप्पणीकार हैं)

(पायनियर से साभार)

आखिरी उम्मीद भी अधूरी

✍ डॉ. मनीषा प्रियम

चुनाव की पूर्व संध्या पर संप्रग-2 का आखिरी आर्थिक दस्तावेज 17 फरवरी को 15वीं लोकसभा के पटल पर रखा गया। संविधान के मुताबिक यह एक वोट ऑन अकाउंट है, न कि अंतरिम बजट, लेकिन अब यही शब्द अधिक प्रचलन में आ गया है। इस प्रावधान के पीछे मंशा यह है कि लोक संग्रह से अर्जित खजाने का हर व्यय लोकसभा द्वारा अधिकृत हो। इस कारण से शायद हम इस दस्तावेज को एक आर्थिक दस्तावेज के रूप में पूर्णत: नहीं आंकें, लेकिन समसामयिक माहौल ऐसा है कि आर्थिक प्रश्न ही अहम बने रहे। राजनीति की बात तो आई, लेकिन आर्थिक नाउम्मीदी और मंदी की पृष्ठभूमि सबसे महत्वपूर्ण रही। जनमानस में कुछ आर्थिक आशाएं थीं, विशेष रूप से मुद्रास्फीति का कड़ा प्रहार और रोजगार में बढ़त न हो पाना। ऐसे में वित्तमंत्री चिदंबरम के अभिभाषण को जब अर्थनीति की कुछ महत्वपूर्ण कसौटियों पर कसा गया तो उत्तर निराशाजनक ही निकला। सबसे पहली बात तो यह कि अपने भाषण की शुरुआत में ही चिदंबरम ने भूमंडलीय आर्थिक परिस्थिति का हवाला दिया। अमेरिका और यूरोप में विस्तृत आर्थिक संकट को ही वह भारत में मंदी के दौर के लिए जिम्मेदार ठहराते रहे। यही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि संकट के इस दौर में भी भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा।

इन कथित जिम्मेदार पहलुओं का हवाला देते हुए भी वह इस बात को बखूबी दबा गए कि अमेरिका और यूरोप, दोनों ही और इनके अलावा जापान भी आर्थिक संकट के काल को अब लगभग पीछे छोड़ चुके हैं। यही नहीं, यदि उनसे सवाल किया जा सकता तो पूछने वाली बात यह भी थी कि आखिर क्यों इस मंदी के दौर में चीन, इंडोनेशिया और तुर्की की स्थिति भारत से बेहतर है। एक तरह से वह इन बातों को गोलकर गए और बखिया उधेड़ने का काम विशेषज्ञों के लिए छोड़ दिया। अच्छा यह होता कि आज उनकी सरकार जब जाने ही वाली है तब वह सदन में इस भाषण में विफलताओं का संज्ञान ले लेते। संसद का पटल लोकसंवाद का एक महत्वपूर्ण जरिया है खासतौर से ऐसे माहौल में जब पूरी कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सीधे प्रसारित की जाती है। यदि आज के दस्तावेज में दिए गए खर्च के लेखा-जोखा को आंका जाए तो दो बातें स्पष्ट रूप से उभरती हैं। पहली बात तो यह कि योजनागत खर्च में बढ़त नहीं है। मोटे तौर पर यही वह व्यय है जो निवेश व विकास का द्योतक है। इसमें बढ़त नहीं होने का मतलब है कि अर्थव्यवस्था के बेस में बढ़ोतरी का कोई काम नहीं हो रहा है और यह व्यय अगर नहीं किया जाए तो निजी निवेशक भी अपनी पूंजी ऐसे माहौल में लेकर नहीं आएंगे। यानी सड़क बनाने का अथवा ऊर्जा उत्पादन का जो काम सरकार को करना चाहिए था उसकी बजाय कुछ और ही रोना रोया जाता रहा।

शायद हम इस दस्तावेज को एक आर्थिक दस्तावेज के रूप में पूर्णत: नहीं आंकें, लेकिन समसामयिक माहौल ऐसा है कि आर्थिक प्रश्न ही अहम बने रहे। राजनीति की बात तो आई, लेकिन आर्थिक नाउम्मीदी और मंदी की पृष्ठभूमि सबसे महत्वपूर्ण रही। जनमानस में कुछ आर्थिक आशाएं थीं, विशेष रूप से मुद्रास्फीति का कड़ा प्रहार और रोजगार में बढ़त न हो पाना। ऐसे में वित्तमंत्री चिदंबरम के अभिभाषण को जब अर्थनीति की कुछ महत्वपूर्ण कसौटियों पर कसा गया तो उत्तर निराशाजनक ही निकला।

अगर सड़क और ऊर्जा पर ध्यान दिया गया होता तो इससे कहीं ज्यादा निवेश हमारे देश में आता। खर्च बढ़ा कहां? खर्च बढ़ा चालू खाते के व्यय में, निवेश में नहीं। यानी सरकार अपना खर्च चलाने के व्यय में ही द्रुतगामी हो चली है। इसी बीमारी का दूसरा नाम है वित्तीय घाटे के छेद का बढ़ना। यूं तो चिदंबरम ने यह कहा कि डेफिसिट में कुछ दशमलव कमी आई है और यह अब 4.6 पर पहुंच गया है, लेकिन सूक्ष्मता से देखने पर यह समझ में आया कि आय और व्यय के बीच खाई बढ़ी ही है और बजट में प्रस्तुत चित्र अकाउंटिंग की सफल कारीगरी का नतीजा है। यानी वित्तीय घाटे के बहुत सारे महत्वपूर्ण अंश या तो बखूबी से गोलकर दिए गए हैं या फिर उन्हें अगले वर्ष के बजट में धकेल दिया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है 35 हजार करोड़ रुपये का तेल का घाटा अगले साल के लिए रख देना। ऐसे में चिदंबरम के इस दावे कि भले ही बढ़त दर अभी कम हो, लेकिन

आने वाली तीसरी और चौथी तिमाही में यह बढ़कर पांच प्रतिशत हो जाएगी, पर शायद ही आर्थिक विशेषज्ञ भरोसा कर सकें। जहां तक आमदनी की बात है वहां भी सरकार विफलताओं से जूझ रही है। टैक्स यानी कर से संग्रहित आमदनी में लगभग 77 हजार करोड़ का घाटा होने की आशंका है। नए टैक्स देने वालों को भी जोड़ा नहीं जा सका है। अर्थात् बढ़ते हुए खर्च और घटती हुई आमदनी का पुराना रोना बना ही रहा। कहीं न कहीं, मुद्रास्फीति में सप्लाई की दशा खराब होने के साथ-साथ सरकारी अपव्यय भी महत्वपूर्ण कारक है।

जहां तक आमदनी की बात है वहां भी सरकार विफलताओं से जूझ रही है। टैक्स यानी कर से संग्रहित आमदनी में लगभग 77 हजार करोड़ का घाटा होने की आशंका है। नए टैक्स देने वालों को भी जोड़ा नहीं जा सका है। अर्थात् बढ़ते हुए खर्च और घटती हुई आमदनी का पुराना रोना बना ही रहा। कहीं न कहीं, मुद्रास्फीति में सप्लाई की दशा खराब होने के साथ-साथ सरकारी अपव्यय भी महत्वपूर्ण कारक है।

चूंकि यह चुनाव के सबसे समीप घोषित सरकारी दस्तावेज है तो लोकलुभावन बातों का दर्ज किया जाना अपेक्षित ही था। इसमें दो बातें उन्होंने की हैं और दोनों ही वोट बैंक पर नजरें गड़ाते हुए की हैं। एक तो उन्होंने छात्रों के कर्ज के मामले में अवधि संबंधी राहत प्रदान की। जो छात्र डॉलर लेकर विदेश में पढ़ रहे हैं उन्हें इससे फायदा होगा, लेकिन जिन्होंने अपना ऋण समय पर चुका दिया है उन्हें ठगे जाने का अहसास भी हुआ है। दूसरा मसला है सेना में वन रैंक वन पेंशन। उन्होंने इस पुरानी मांग को स्वीकार कर लिया। इसके अलावा निर्भया फंड, मनरेगा और आधार के लिए उन्होंने खर्च बरकरार रखा। यहां सवाल यह है कि निर्भया फंड में पिछले साल भी दिए गए धन का अब तक खर्च करने का कोई ढांचा नहीं उभर पाया है। इससे सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े होते हैं। उसके पास सामाजिक योजना में खर्च का कोई विजन है भी या नहीं, यह एक बड़ा सवाल है। उसे बताना चाहिए कि अगर खर्च नहीं हो पाया तो किन कारणों से नहीं हो पाया? आधार कार्ड पर आज भी यही प्रश्न बना रहा कि जिस नीति को सरकार ही नहीं समझ पा रही है, उसे केवल किसी का मन रखने के लिए क्यों आगे बढ़ाया जा रहा है? आधार कार्ड पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

आज जब सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि यूआइडी को कल्याणकारी योजनाओं के साथ जबरदस्ती नहीं जोड़ा जा सकता तब भी भी बजट में उसके लिए प्रावधान किया गया। जहां तक फूड सब्सिडी का सवाल है उसमें भी राशि पिछले वर्ष के बराबर या कम ही रही। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि कल्याणकारी योजनाओं में सरकारी ढपली बजाई गई और जमीन पर क्या हो रहा है, इससे किनारा कर लिया गया। अंत में चिदंबरम ने एक अनदेखे भविष्य के लिए दस बिंदुओं की तरफ संकेत देते हुए सदन की चेतना को जाग्रत किया और यह बताया कि आगे के लिए हमें क्या करना चाहिए, लेकिन जिस सरकार की मियाद अब कुछ दिनों की है उसके वित्तमंत्री से ऐसे बयान में संसद को भी और भारत के सचेत नागरिकों को भी बड़बोलेपन का एक नया अंदाज दिखा। अंत में चिदंबरम ने अमर्त्य सेन और ज्यां द्रेज के नाम की गुहार लगाई। ये दोनों अर्थशास्त्री सोनिया गांधी के निकट माने जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने तमिल कवि तिरुवल्लुवर की कुछ पंक्तियां संसद को सुनाई। कहीं तमिल में पढ़ी गई ये पंक्तियां जयललिता की ओर इशारा तो नहीं कर रहीं? चिदंबरम के लिए शिवगंगा जाने का वक्त हो चुका है। ■

(लेखिका लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में रिसर्च स्कॉलर रही हैं।)

(दै. जागरण से साभार)

सांसद राव इंद्रजीत सिंह एवं आर.के. सिंह भाजपा में शामिल

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में श्री राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस सांसद, गुड़गांव (स्वतंत्रता सेनानी स्व. राव तुला राव जी के परपौत्र, स्व. विरेन्द्र सिंह पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के सुपुत्र) व श्री आर.के. सिंह (माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा सराहनीय राजपत्रित, देशभक्ति से ओत-प्रोत 39 वर्षों तक भिन्न-भिन्न पदों को सुशोभित करते हुए, पुलिस महानिरीक्षक (सीआरपीएफ, सेवानिवृत्त) भाजपा में शामिल हुए। दोनों ही महानुभावों ने गहन मंथन और विश्लेषण के बाद देश की सेवा करने हेतु 13 फरवरी 2014 को भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। ■

गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ अमेरिकी राजदूत सुश्री नैंसी पॉवेल ने की भेंट

त्वरित निर्णय और स्पष्ट प्रशासनिक प्रक्रिया के चलते गुजरात से खुश है अमेरिकी उद्योगजगत : पॉवेल

गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से अमेरिकी राजदूत सुश्री नैंसी पॉवेल सहित अन्य अमेरिकी अधिकारियों ने 13 फरवरी को गांधीनगर में मुलाकात की।

सुश्री पॉवेल ने श्री नरेन्द्र मोदी के साथ वृहद वैश्विक प्रवाहों के सन्दर्भ में भारत-अमेरिका के बीच संबंधों को तेज तथा प्रशासनिक प्रक्रिया को बेहद स्पष्ट बताते हुए अमेरिकी राजदूत ने कहा कि इन्हीं वजहों से अमेरिका का उद्योगजगत गुजरात से खुश है।

सुश्री पॉवेल ने कहा कि गुजरात के प्रशासनिक अभिगम के अलावा संस्थागत प्रसूति के जरिए माता और शिशु के स्वास्थ्य में सुधार लाने वाली चिरंजीवी

योजना जैसी योजनाओं का अनुसरण यदि अन्य विकासशील देश भी करें तो वहां के लोगों को इसका लाभ अवश्य मिलेगा।

अफगानिस्तान की वर्तमान परिस्थिति के संबंध में उन्होंने अफगानिस्तान के अधिकारियों तथा वहां की ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भरता का प्रशिक्षण देने को लेकर विस्तार से चर्चा की। श्री नरेन्द्र मोदी ने सुझाव दिया कि सहकारी डेयरी उद्योग क्षेत्र का गुजरात का मॉडल अफगानिस्तान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अहम साबित हो सकता है। इस सुझाव का स्वागत करते हुए सुश्री पॉवेल ने स्वयं इस दिशा में आगे कदम बढ़ाने की तत्परता व्यक्त की।

पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक भागीदारी की मजबूत नींव डाले जाने की रूपरेखा पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने भारत के पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध के लिए श्री वाजपेयी द्वारा किए गए प्रयासों की जानकारी दी। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि अमेरिका के साथ संबंधों को ज्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने न्यूयार्क में भारतीय महिला राजनयिक के साथ हुए दुर्व्यवहार के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए आशा जतायी कि इस परिस्थिति का जल्द ही स्थायी हल निकाल लिया जाएगा। अमेरिकी राजदूत ने भरोसा दिलाया कि इस मुद्दे के त्वरित समाधान के लिए अमेरिकी सरकार प्रतिबद्ध है।

श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत एवं अमेरिका के बीच व्यूहात्मक भागीदारी को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए यह जरूरी है कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

मुख्यमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए एक वैश्विक मापदंड बनाने की हिमायत की और 26-11 के मुंबई हमले के गुनहगारों को तेजी के साथ कानूनी सजा देने पर जोर दिया।■

ज्यादा मजबूती प्रदान करने के साथ ही पारस्परिक सहयोग को लेकर विस्तार से चर्चा की।

इससे पूर्व की अपनी गुजरात यात्राओं का सुखद स्मरण करते हुए सुश्री नैंसी पॉवेल ने पुनः गुजरात यात्रा का अवसर मिलने को लेकर खुशी जतायी। सुश्री पॉवेल ने कहा कि गुजरात में विकास के विविध क्षेत्रों में हुए सकारात्मक परिवर्तन और राज्य की गति से वे प्रभावित हुई हैं। गुजरात में निर्णय निर्धारण की प्रक्रिया को अत्यंत

सीआईआई राष्ट्रीय परिषद बैठक

भाजपा ने गिनाईं अपनी आर्थिक प्राथमिकताएं

गत 17 फरवरी, 2014 को सीआईआई राष्ट्रीय परिषद को संबोधित करते हुए भाजपा के कोषाध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य श्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 10 वर्षों में 200 मिलियन रोजगार के अवसर उत्पन्न करना पार्टी की प्राथमिकता रहेगी। श्री गोयल ने इस विषय पर अफसोस प्रगट किया कि पिछले कुछ वर्षों में उच्च विकास के बाद भी देश में रोजगार-सृजन के मामले में बेहद हताशा मिली है और केवल 2.5 मिलियन रोजगार पैदा हुए जबकि केवल आवास क्षेत्र से ही मैन्युफैक्चरिंग में इतनी वृद्धि की जा सकती थी। उन्होंने कहा कि यदि देश 100 मिलियन सस्ते मकानों के निर्माण का एजेण्डा हाथ में ले लेता उससे ही बड़ी आसानी से हर वर्ष 15 मिलियन रोजगार पैदा किए जा सकते थे।

नौकरियों का सवाल निपुणता विकास के साथ जुड़ा है। खेद की बात है कि राष्ट्रीय निपुणता विकास परिषद (एनएसडीसी) के इन तमाम वर्षों में उतनी धनराशि प्राप्त नहीं हो सकी जितनी धनराशि का वायदा किया गया था, जिससे केवल 3 लाख लोगों को ही निपुणता प्राप्त हो सकी जबकि इससे कई गुना लोगों की प्रशिक्षित किया जा सकता था। उनका सुझाव था कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमएनआरईजीएस) से 200 मिलियन लोगों को दक्ष बनाया जा सकता है ताकि वास्तव में लोगों को निपुणता प्राप्त करने के लिए धनराशि उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि पर्यटन, मैन्युफैक्चरिंग (विनिर्माण), आवास और इंफ्रास्ट्रक्चर चार ऐसे क्षेत्र हैं जहां दक्षता काम कर सकती है। माल और सेवाकर (जीएसटी) के एक प्रश्न का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा इसके खिलाफ नहीं है बशर्ते कि कुछ मुद्दों का समाधान कर लिया जाए। इन मुद्दों में प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राज्य की जरूरतों जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। श्री गोयल ने आगे कहा कि यदि ये जटिल प्रश्न हल कर लिए जाते हैं तो भाजपा को जीएसटी की स्वीकृति पर कोई एतराज नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर सरकार को मुआवजे की राशि बढ़ाना चाहिए और इसकी प्रक्रिया सरलीकरण होनी चहिए, परंतु जैसा कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली ने कहा कि बस कठोर कानून बना दिया गया, जबकि उनका कहना था कि चार-पांच सेक्टरों को दायरे से अलग रखना चाहिए था क्योंकि इससे पूरे का पूरे बिजनेस में गतिरोध पैदा हो जाता है।

जब तक देश का मैन्युफैक्चरिंग आधार को मजबूत नहीं किया जाता है तब तक भारत में विदेशी ब्रांडों को आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इससे देश की व्यवस्था और आपूर्ति को मजबूती नहीं मिल पाएगी।

श्री गोयल ने रिटेल में मल्टी-ब्रांड एफडीआई पर पार्टी के विरोध की बात करते हुए कहा कि जब तक देश का मैन्युफैक्चरिंग आधार को मजबूत नहीं किया जाता है तब तक भारत में विदेशी ब्रांडों को आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इससे देश की व्यवस्था और आपूर्ति को मजबूती नहीं मिल पाएगी।

श्री गोयल ने कहा कि भाजपा नेता श्री नरेन्द्र मोदी को पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता मिलनी चाहिए और इस प्रकार से उन्होंने सकारात्मक और आशाजनक रूप से अपने भाषण को समाप्त किया। ■

आदर्श घोटाला

भाजपा ने की महाराष्ट्र के राज्यपाल को वापस बुलाने की मांग

गत 11 फरवरी 2014 को भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने आदर्श घोटाले में श्री अशोक चव्हाण के खिलाफ जांच की मंजूरी के लिए सीबीआई के आवेदन को ठुकराने के महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री के. शंकर नारायण के तरीके के विरोध में महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में महाराष्ट्र के राज्यपाल को वापस बुलाने की मांग की गयी। इस प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा में विपक्ष के नेता सर्व श्री अरुण जेटली, लोकसभा में भाजपा के उपनेता गोपीनाथ मुंडे, अनंत गीते, देवेंद्र फडनवीस, राजू शेट्टी, रामदास अठावले, विनोद तावड़े, संजय राउत, महादेव जानकर, आशीष शेल्लार एवं किरीट सोमैया शामिल थे। हम इस ज्ञापन का पूरा पाठ प्रकाशित कर रहे हैं:

श्री प्रणव मुखर्जी
महामहिम राष्ट्रपति, भारत

विषय : महाराष्ट्र के राज्यपाल को वापस बुलाने के लिए

संदर्भ : आदर्श घोटाला/श्री अशोक चव्हाण के खिलाफ जांच और उसकी मंजूरी

आदर्श घोटाले में श्री अशोक चव्हाण के खिलाफ जांच की मंजूरी के लिए सीबीआई के आवेदन को ठुकराने के महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री के. शंकर नारायणन के तरीके को लेकर हम चिंतित है।

अवलोकन के मुख्य बिन्दु :

- श्री अशोक चव्हाण के खिलाफ मुकद्दमा चलाने के आवेदन की अस्वीकृति देना।
- मंजूरी के लिए आवेदन को निरस्त करने के लिए कोई उचित संदर्भ नहीं।
- पाटिल आयोग की रिपोर्ट में श्री अशोक चव्हाण के विरूद्ध पर्याप्त सबूत।
- आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि प्रथम दृष्टया मुकद्दमा कहा है।
- आयोग की रिपोर्ट के पैरा 69 और उसके बाद स्पष्ट तौर पर कहा है कि श्री अशोक चव्हाण द्वारा प्रतिदान किया गया।
- आयोग की रिपोर्ट पैरा 79 में पैनल एक्शन की सिफारिश की गई है।
- यहां तक कि महाराष्ट्र सरकार की एक्शन टेकन रिपोर्ट में क्षतिपूर्ति के लिए कहा गया।
- एक्शन टेकन रिपोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ने सिफारिश की कि उन सभी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाये, जिनके नाम पैरा 69 में दिये गये हैं। एटीआर यह बतलाती है कि सीबीआई ने श्री अशोक चव्हाण सहित 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की हैं। अत: किसी अन्य एफआईआर की आवश्यकता नहीं है।
- आयोग की रिपोर्ट, अप्रैल 2013 में सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई।
- श्री अशोक चव्हाण के विरूद्ध मुकद्दमे की मंजूरी को रोकने के लिए जो विभिन्न और अनुकूल अवलोकन थे केवल उन्हीं अंशों को राजभवन ने स्वीकार किया।
- राज्य सरकार/राजभवन/राज्यपाल ने जानबूझकर पाटिल आयोग के उन अंशों/निंदा/सिफारिशों की अनदेखी की, जिनमें श्री अशोक चव्हाण के विरूद्ध कार्रवाई और क्षतिपूर्ति की बात थी।
- यहां तक कि आदर्श घोटाले पर संसद की पीएसी ने मौन सहमति, भ्रष्टाचार माना था और श्री अशोक चव्हाण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही थी।
- राज्यपाल के द्वारा अनुमति न दिए जाने के कारण सीबीआई ने श्री अशोक चव्हाण को दोषी के रूप में नाम हटाने के लिए स्पेशल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
- महाराष्ट्र के राज्यपाल उचित परिप्रेक्ष्य में संज्ञान लेने के असफल रहे। यद्यपि राज्यपाल लोकहित में श्री अशोक चव्हाण के विरुद्ध अनुमति देने को बाध्य थे, परन्तु उन्होंने श्री अशोक चव्हाण को स्वतंत्र छोड़ दिया।

इन परिस्थितियों में हम महाराष्ट्र के राज्यपाल को वापस बुलाने की मांग करते हैं। ■

नासकॉम इंडिया लीडरशिप फोरम

भारत में आईटी रिवॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए डिजिटल इंडिया की ब्रांड इमेज खड़ी करें : नरेन्द्र मोदी

गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मुंबई में चल रहे नासकोम के इंडिया लीडरशिप फोरम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए भारत में तेजी से

प्रभावी आकार ले रहे आईटी रिवॉल्यूशन को केन्द्र में रखते हुए डिजिटल इंडिया की ब्रांड इमेज खड़ी करने का देश के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र के संचालकों को प्रेरक आह्वान किया।

नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (नास्कॉम) की स्थापना के 25वर्ष पूरे होने पर आयोजित फोरम को संबोधित करने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री को निमंत्रण दिया गया था। फोरम में 23 देशों के 1400 आईसीटी प्रतिनिधि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया कि नास्कॉम आईटी रिवॉल्यूशन के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का नेतृत्व करे। श्री मोदी ने प्रेरक सुझाव दिया कि नास्कॉम अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एजेंडे में प्राथमिक शिक्षा में बच्चों की ड्रॉप आउट की समस्या पर फोकस कर स्कूल जाने वाले बच्चों के ट्रेकिंग का डाटा सॉफ्टवेयर विकसित करे। श्री मोदी ने कहा कि आईटी हिन्दुस्तान को जोड़ने में, गति प्रदान करने में और सोच बदलने में सशक्त भूमिका अदा कर सकती है।

इस सन्दर्भ में मुख्यमंत्री ने आईटी की विस्तृत भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा-

- आईटी देश के दूरदराज के हिस्सों को एक सूत्र में बांध सकता है
- आईटी समाज में संवाद का वातावरण बना सकता है
- आईटी जनता और सरकार के बीच सेतु बन सकता है
- आईटी सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का समन्वय कर उसे परिणामलक्षी बना सकता है
- आईटी मांग और पूर्ति के बीच की खाई को पाट सकता है
- आईटी हमें अमूल्य ज्ञान के खजाने के निकट ला सकता है।
- आईटी हमें महत्वपूर्ण प्रवाहों के संपर्क में रहने में मदद करता है

भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है, इसका उल्लेख करते हुए श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि देश की लगभग 65 फीसदी आबादी 35 वर्ष से कम आयु वर्ग की है। इस युवाधन की क्षमता, ऊर्जा और प्रतिभा सिर्फ देश के लिए ही नहीं बल्कि समग्र विश्व के लिए नया इतिहास रचने की ताकत रखती है। जरूरत इन युवाओं को हुनर-कौशल्य से सशक्त बनाने की है, ताकि अपने व्यक्तिगत विकास के अलावा यह युवाधन देश का विकास भी सुनिश्चित कर सके। नासकॉम इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। हमारा आईटी उद्योग और आईटी क्षेत्र की मानव संपदा ने दुनिया में भारत की एक बेहतर छवि स्थापित की है। अब समय आ गया है कि भारत में आईटी क्रांति आकार ले।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में 85 करोड़ मोबाइल फोन है। देश की लगभग एक चौथाई आबादी के पास इंटरनेट की सुविधा है। इसके बावजूद अपने दैनंदिन जीवन के लिए उपयोगी आईटी ज्ञान लोगों में नहीं है। यदि आईटी को लोगों के जीवन का उपयोगी हिस्सा बनाएंगे तो आईटी इंडस्ट्रीज का बाजार अपनेआप तरक्की करेगा। इसके लिए आईसीटी क्षेत्र में तालीम की जरूरत है। इस सन्दर्भ में मुख्यमंत्री ने गुजरात द्वारा एम्पॉवर नामक कार्यक्रम शुरू किए जाने की भूमिका पेश की।

नये भारत के निर्माण में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्रोथ इंजन बन सकता है, ऐसा स्पष्ट रूप से कहते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा कि नये भारत से संबंधित उनका विजन डिजिटल इंडिया

बनाने का है।

डिजिटल डिवाइड के संबंध में चर्चा करते हुए श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि डिजिटल डिवाइड का असंतुलन बढ़ेगा तो वह अनेक नये संकट पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि 'डिजिटल डिवाइड' को दूर करने का कार्य हमारी प्राथमिकता है।

उनके मुताबिक डिजिटल डिवाइड अर्थात् शहर में कोई व्यक्ति आईटी के द्वारा जो प्राप्त कर सकता है, वह अंदरूनी गांवों में रहने वाले व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है, ऐसी असमानता को दूर करने की जरूरत पर उन्होंने बल दिया। गुजरात में डिजिटल डिवाइड को कुछ हद तक दूर करने का मार्ग ढूंढा है। राज्य में 1400 ई-ग्राम केन्द्र ग्रामीण लोगों को अनगिनत सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। गुजरात में वन-डे गवर्नेन्स केन्द्र वीजा कार्यालय की सेवा उपलब्ध कराते हैं। गुजरात ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक वितरण और कृषि क्षेत्रों के लिए आईटी का व्यापक फलक पर विनियोग किया है, इसकी विषद भूमिका भी उन्होंने दी।

सायबर वार में नई चुनौतियों के सामने आईटी प्रोफेशनलों से पूरी तैयारी के साथ अपनी भूमिका निभाने का आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सायबर सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। जिन लोगों को आईटी का पर्याप्त ज्ञान नहीं है वे सुरक्षा के खतरों से अनजान होते हैं। हालांकि, जिन लोगों को इसकी जानकारी होती है, उन्हें मालूम है कि सायबर सिक्योरिटी अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है। हम ऐसे जमाने में रहते हैं जहां युद्ध अब सायबर स्पेस में होंगे। इसलिए हमें इन चुनौतियों का सामना करने की दिशा में कार्य करना होगा। ■

पृष्ठ 14 का शेष...

उम्मीदों से कहीं ज्यादा कम है जहां इससे कहीं अधिक व्यय की आवश्यकता है। वर्ष-दर-वर्ष ईंधन पर सब्सिडी कम होती चली जा रही है। वित्त मंत्री ने फिर एक बार अगले राजकोषीय के लिए 35,000 करोड़ रुपए कम सब्सिडी कर दी है। यह मात्र एक सांख्यिकीय भ्रम पैदा करने वाला है ताकि राजकोषीय घाटे को कम दिखाया जा सके जबकि इसका मुद्रास्फीति प्रभाव अर्थव्यवस्था पर वास्तव में बना रहेगा। वित्त मंत्री ने एक बार फिर OROP अर्थात् एक रैंक एक पेंशन योजना की ताल बजाई है और 500 करोड़ रुपए को रक्षा पेंशन खाते में अंतरित कर दिया है। यूपीए सरकार रक्षा कर्मिकों के हित में मुंहजबानी काम करती है। 2009-10 के पहले बजट में एक समिति बनाई गई थी और इसकी सिफारिशों के कार्यान्वयन की बात कही गई थी। परन्तु शिकायतें ज्यों की त्यों बनी रहीं क्योंकि वे अधकचरी थीं। वित्त मंत्री ने फिर वायदा किया है इस हित को इस बजट में पूरी तरह से हल कर दिया गया है। हमारी फौजों की महत्वाकांक्षाओं पर किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।

हालांकि लेखानुदान चार महीने के लिए हैं, परन्तु विकास दर, वास्तविक राजकोषीय घाटा, मुद्रास्फीति, निवेश और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की धीमी गति बहुत बड़ा चिंता का विषय है। रुपए की स्थिरता विशेष रूप से चिंता का विषय है क्योंकि रुपया एक अस्वीकार्य स्तर तक जा पहुंचा है। क्या वित्त मंत्री अगले वित्त मंत्री के लिए जो विरासत छोड़कर जाएंगे, वे इस पर गंभीरता से आत्मचिंतन करेंगे? वित्त मंत्री तो आज राहत महसूस कर रहे हैं। परन्तु उनका उत्तराधिकारी संकट में पड़ गया है।■

पृष्ठ 15 का शेष...

लिए आकर्षण का केन्द्र बनी रहती है।

कर्नाटक के सभी शहरों में रेलवे स्टेशनों और यात्रियों की भी उपेक्षा की जाती है और पिछले दस वर्षों से कोई सुधार नहीं हुआ है। आम आदमी के लिए महीनों पहले भी आरक्षण करा कर कन्फर्म टिकट प्राप्त करना परेशानी वाला अनुभव बन चुका है और यही देखा गया है कि सभी टिकट बिक चुके होते हैं। सरकार की कोई भी इच्छा-शक्ति नहीं है कि वह लोगों को समुचित अवसर प्रदान कर सके और इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हो सके। गाड़ियों की हालत और सुविधाएं अभी तक वैसी ही बनी हुई हैं जैसी की दस वर्ष पहले थीं। अन्य जोनों में तो हमें नए डिजाइन की कोचें देखने को मिल जाती हैं, परन्तु कर्नाटक में हम लोगों को उन्हीं बिगड़ी हालत वाली कोचों में यात्रा करनी पड़ती हैं।

प्रमुख गाड़ियों में सुरक्षा की घटनाएं होने की पूरी उपेक्षा की गई है जिसके कारण बहुत से लोगों के प्राण चले जाते हैं, जिसके लिए हम उदाहरण के रूप में पिछले दो वर्षों के उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं:

- 28.12.2013 को अनंतपुर जिले में बंगलौर-नांदेड में अग्नि-कांड।
- 10.4.2013 को अर्राकोणम के नजदीक मुजफ्फरपुर-यशवंतपुर एक्सप्रैस में गाड़ी का पटरी से उतरना।
- 19.12.2012 को मेडक जिले में इंदौर-यशवंतपुर एक्सप्रेस का दुर्घटना होना।
- 22.5.2012 को पेनुकोंडा के निकट हुबली-बंगलौर हैम्पी एक्सप्रेस का मालगाड़ी से टकराना। ■